आज का विचार
खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं है। किसी के लिए जरूरी होना भी बहुत खूबसूरत होता है।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

3

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 92, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

ऐतिहासिक नगर बटाला के विकास को बड़ा बढ़ावा, मान द्वारा 177 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा

बटाला क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 42.56 करोड़ रुपये और मंडी बोर्ड द्वारा 34.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
बटाला

पंजाब के ऐतिहासिक शहरों में शामिल बटाला के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 177 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। ऐतिहासिक नगर के बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने सत्ता का सुख भोग चुकी पिछली सरकारों को कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। यहां की नगर निगम द्वारा 95.72 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये जाएंगे, मंडी बोर्ड द्वारा 16.05 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण पर 65.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों के नवीनीकरण पर मंडी बोर्ड 42.56 करोड़ रुपये जबकि लोक निर्माण विभाग 34.97 करोड़ रुपये खर्च करेगा। बटाला हलके में चार नए पुल बनेंगे और नई पुलिस लाइन के लिए 14.81 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने साल 2022 में अकाली-कांग्रेस की तीन पीढ़ियों से चल रही लूट का अंत कर दिया और साल 2027 में भी उन्हें वापसी नहीं करने देंगे, जबकि पिछली सरकारों पर खुद को बचाने के लिए जानबूझकर बेअदबी विरोधी कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने पारंपरिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां आम लोगों से दूर हो गई थीं जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें खारिज कर दिया जबकि उनकी सरकार शासन प्रदान करने और जवाबदेही के सम्मिलन के साथ आगे बढ़ रही है।

कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, अकालियों ने जानबूझकर बेअदबी के खिलाफ कमजोर कानून बनाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घिनौने अपराध के दोषियों को उनके पापों की सजा न मिले। उन्होंने आगे कहा, ये नेता यह भी डरते थे कि उन्हें भी उनके अपराध की सजा मिलेगी जिस कारण इन्होंने कानून ही कमजोर बना दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने जगत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसमें बेअदबी के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का घिनौना अपराध प्रांत में कठोर मेहनत से कायम की गई शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने की गहरी साजिश थी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कानून अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, अब इस अक्षम्य अपराध में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा और बाकियों के लिए अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के पिता हैं और प्रांत सरकार इस पवित्र ग्रंथ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, अगर पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही प्रांत में सुरक्षित नहीं है तो यह और कहां हो सकता है। इस कानून को बेअदबी रोकने के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। अकाली दल की तथाकथित बचाओ यात्रा पर व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, अकाली दल की इस यात्रा का असली नाम परिवार बचाओ यात्रा है क्योंकि यह सारा प्रयास उनके पारिवारिक हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने अकाली नेतृत्व को चुनौती देते हुए पूछा, 15 साल प्रांत को लूटने के बाद वे किससे प्रांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा है, पंजाबियों के मनों को गहरी ठेस पहुंचाई है और विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पारंपरिक पार्टियों के लोक-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण उनसे मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब और पंजाबियों से अधिक अपने परिवारों की चिंता करती थीं, जिस कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगीः मोदी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में परिसीमन के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होने का आश्वासन देते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की और कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा, हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जब-जब चुनाव आया है, जिस दल ने महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। मोदी ने कहा, 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब ने (2023 में) सहमति से इसे (महिला आरक्षण विधेयक) पारित किया था। किसी का राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इतिहास गवाह है कि यह किसी के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय के पक्ष में जाएगा। जिन्हें इसमें राजनीति की बू आ रही है। वे खुद के 30 साल के परिणामों को देख लें। उनका इसमें ही फायदा है। नुकसान से बच जाएंगे। राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। जो विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए विधेयक एक साथ लाने पर और कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होने संबंधी कुछ विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, संविधान ने हमें यहां बैठकर देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। ना टुकड़ों में सोच सकते हैं, न टुकड़ों में निर्णय ले सकते हैं। निराधार बात है, इसमें रत्ती भर सचाई नहीं है।

उन्होंने कहा, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो पश्चिम हो, छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों..... निर्णय प्रकिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। मोदी ने कहा, अतीत में जो सरकारें रहीं, जिनके कालखंड में परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।

जब तमिलनाडु की एक सांसद ने गारंटी देने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने कहा, अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा शब्द चाहें ते इसका इस्तेमाल करता हूं। तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो उसका इस्तेमाल करता हूं। नीयत साफ है तो शब्दों का खेल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 25-30 साल पहले महिला आरक्षण का विचार आया था तभी इसे लागू कर दिया जाना चाहिए था।

प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को लिया निशाने पर

उन्होंने कहा, हम सब भाग्यवान हैं कि हमें देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सा बनाने का सौभाग्य मिला है। मोदी ने कहा कि हम सभी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। यह उसका अधिकार है। उन्होंने कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय-समय पर सभी ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का समर्थन तो किया लेकिन किसी न किसी बहाने से इसे रोकने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा तरह-तरह की बहानेबाजी और चीजों को उलझाना अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे इसका राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को इसका लाभ नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित हो जाए मैं कल विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद देकर, सबकी तस्वीर छपवाने को तैयार हूं। सामने से श्रेय का ब्लैंक चैक आपको दे रहा हूं। उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत में कहा, राष्ट्र जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैद करके एक राष्ट्र की अमानत बना देते हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देते हैं। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसा ही पल है। उन्होंने कहा, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तो तय करेगा ही, देश की दशा और दिशा भी तय करने वाला है। मोदी ने कहा, हम पहले ही देरी कर चुके हैं। कारण कुछ भी हों, जिम्मेदार कोई भी हो। मोदी ने कांग्रेस की सरकार में पंचायतों में आरक्षण दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय ऐसी चर्चा होती थी कि पंचायतों में आरक्षण आराम से दे देते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें खुद का पद जाने का डर नहीं लगता।

आसनसोल में गरजे योगी, बोले - भाजपा सरकार बनी तो खत्म होगा माफिया राज

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता,

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घरों की छतों, वाहनों और पेड़ों तक पर चढ़े नजर आए। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ था। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर हमला बोला और राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज अराजकता, दंगे और माफिया राज का माहौल है। विकास के लिए आने वाला पैसा कटमनी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य को टेरर, माफियाराज और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, जिससे आम जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया का बोलबाला है और ये लोग राज्य के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाले विकास के धन को भी हड़प लिया जाता है और जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंचता।

हमने यूपी को बनाया दंगामुक्त राज्यः योगी

मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि अरिजीत का अर्थ ही होता है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे, इसलिए जनता को उन्हें जीताकर राज्य में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने पर राज्य की सभी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग नौ वर्ष पहले वहां भी यही स्थिति थी, जहां हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे, अपराध चरम पर था और माफिया का दबदबा था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद वहां कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब न दंगे होते हैं और न ही कर्फ्यू लगता है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने अयोध्या में बने भगवान श्रीराम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल इस निर्माण को रोक नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी गोमाता की रक्षा और समाज को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिसीमन के जरिए राजनीतिक हित साध रही सरकारः प्रियंका

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को धर्मसंकट में डालकर मनमानी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात कह कर सरकार परिसीमन के माध्यम से चुनावी हित साधना चाहती है। प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन और उसके माध्यम से देश में महिला आरक्षण लागू किए जाने से जुड़े संविधान संशोधन एवं दो अन्य विधेयकों पर जारी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश को गुमराह कर रही है और कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के इस प्रयास का डटकर विरोध करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है ताकि वह जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से बच सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत का इजाफा कर रही है लेकिन इससे जुड़े अधिनियम में यह कैसे किया जाएगा, इसके बारे में साफ नहीं है। सरकार केवल खोखले आश्वासन दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि विधेयक में संसद का 50 प्रतिशत विस्तार प्रस्तावित है लेकिन इसके लिए किसी ठोस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इतने बड़े परिवर्तन में क्या नियम होंगे, कैसे किया जाएगा, इस बारे में विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में देश के हर राज्य की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई और इस पर बदलाव लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के जरिए यह सब बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री के खोखले वादों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन में बदलाव किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि असम में सरकार ने विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों को काटा और अपने राजनीतिक फायदे के लिए मनचाहे तरीके से नई सीमाएं तय कीं। यही काम अब पूरे देश में करने की तैयारी की जा रही है।

राज्यों का नहीं घटेगा प्रतिनिधित्व, परिसीमन भी पहले जैसी प्रक्रिया से होगाः शाह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि से राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनित्व प्रतिशत पहले के भांति बना रहेगा। वहीं, सरकार पिछली बार देश में हुई परिसीमन की प्रक्रिया को ही दोहराएगी। इससे जुड़ा विधेयक कांग्रेस के परिसीमन अधिनियम जैसा ही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से लाए गए तीन विधायकों से जुड़ी भ्रांतियां को दूर करने के लिए लोकसभा में आज चर्चा का संक्षिप्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह विषय पर विस्तार से अपनी बातचीत कल रखेंगे लेकिन इस मुद्दे पर वे आज कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके ठीक बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज रात भी इस पूरे विषय पर कोई भ्रांति ना हो इस उद्देश्य से वह संक्षिप्त रूप से अपनी बातचीत रखना चाहते हैं।' अमित शाह ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए वर्तमान सीटों में 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। 543 में 50 प्रतिशत सीटें जोड़ने से आंकड़ा 816 होता है और 850 असल में राउंडअप फिगर है। वर्तमान में भी 543 पूर्ण आंकड़ा नहीं है।

उन्होंने कहा कि परिसीमन और सीटों में बढ़ोत्तरी के बाद दक्षिण भारत के राज्यों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होगी और उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23 हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण भारत के सभी पांच राज्यों की वर्तमान में 129 लोकसभा सीटें हैं और प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है। यह बढ़कर 195 हो जाएंगी और प्रतिनिधित्व 23.97 प्रतिशत हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। वह बताना चाहते हैं कि सरकार ने पहले ही जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। वर्तमान में घरों की गिनती की जा रही है और इस कारण इससे जुड़े फॉर्म में जाति का उल्लेख नहीं है।'

सभी नगर निकायों में एक मई से दो सप्ताह तक चलेगा स्पेशल स्वच्छता अभियानः नायब सिंह सैनी

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य के सभी नगर निकाय संस्थानों में आगामी एक मई 2026 से दो सप्ताह के लिए स्पेशल स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, इस अभियान के अलावा वर्षभर चलने वाले सफाई कार्यों में वार्ड समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रहेगी।

उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी जिमेदारी समझकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ₹स्वच्छ भारत मिशन₹ के विजन को लक्ष्य तक पहुंचाना है। स्वच्छता के मामले में बेहतरीन कार्य करने वाले वार्डों को रैंकिंग के आधार पर उनको इन्सेंटिव देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों में नवगठित वार्ड समितियों के सदस्यों से रुबरु हो रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था लोगों की सहभागिता से ही संभव है , क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता की स्वयं जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाना संभव नहीं है। उन्होंने समिति के सदस्यों से आान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के शहरी नगर निकाय में कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार से मिलकर उनके वाहन का रुट प्लान इस तरह से तैयार करें कि हर घर तक वाहन पहुंचे और सभी घरों का समय पर कूड़ा उठान सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने इन सदस्यों से स्वच्छता अभियान के लिए सुझाव देने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि अच्छे सुझावों पर गौर करके उनको कार्य में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वार्ड समिति के इन सदस्यों को जनता और सरकार के मध्य एक सेतु बताते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी कूड़े के उठान से संबंधित उनकी शिकायत नहीं सुनता है तो राज्य मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा जिस पर वे अपनी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि निर्धारित स्थान की बजाए अन्य स्थान पर कूड़ा फेंकने वाले नागरिकों को समझाएं, टोकें, फिर धीरे-धीरे उनका भी मूड बदलने लगेगा और वे भी स्वच्छता में सहभागी बन जाएंगे। उन्होंने नुक्कड़ नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जागरूक करने की बात कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव श्री यशपाल तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मिशन-निदेशक श्री शाश्वत सांगवान के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएफएमएस पर लंबित फाइलों का 15 दिन में निपटारा करें सुनिश्चितः नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफएमएस पोर्टल पर लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित फाइलों का निपटारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां सिविल सचिवालय में मैन रिसोर्स मॉड्यूल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर सीएफएमएस में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करें और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर फाइलों को समय-समय पर अपडेट करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर महीने इसकी नियमित समीक्षा की जाए और वे स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

हिमाचल के कबड्डी खिलाड़ियों को भी मिले डीएसपी का पद : टेकचंद शर्मा

सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी भावना ठाकुर को सम्मानित किया

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी भावना ठाकुर को युवाओं की प्रेरणा स्रोत अवार्ड से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया । जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष टेकचंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल से अपनी पहचान बनाई है तथा हिमाचल का सिर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री द्वारा कबड्डी खिलाड़ी भावना ठाकुर को सम्मानित करना कबड्डी संघ के लिए बहुत बड़ा सम्मान है।

उन्होंने कहा कि इस सम्मान के साथ-साथ इन बेटियों को हिमाचल पुलिस में डीएसपी पद से नवाजा जाए। हिमाचल के कबड्डी खिलाड़ियों ने विपरीत परिस्थितियों में अपना बेहतर प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। हिमाचल के युवा व युवतियां प्रो. कबड्डी में खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों की बदौलत अब नए युवा खिलाड़ी भी कबड्डी खेल को अपनी आजीविका से जोड़ रहे हैं जो एक अच्छी बात है। जो युवा खेल के मैदान अपना पसीना बहाता है वह कभी भी नशे का आदी नहीं होता। सरकार प्रयास करें की प्रदेश का हर युवा खेल के मैदान तक पहुंचे भावना ठाकुर, अजय ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, शिवांश ठाकुर सुभाष शर्मा गन्नू और अन्य खिलाड़ियों ने अटैक प्रयास करके नाम कमाया है तथा हिमाचल का नाम भी रौशन किया है। हरियाणा सरकार ने अपने खिलाड़ियों को पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अन्य विभागों में भी नियुक्तियां दी है जिससे वहां के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति बैठकः सरकार-संगठन तालमेल पर चर्चा, महिला आरक्षण मुद्दे पर सुक्खू ने भाजपा को घेरा

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद गुरुवार को शिमला स्थित राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बैठक शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई मंत्री, पार्टी विधायक, जिला अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर बनाने और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच पूरा समन्वय है और दोनों मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं, इसलिए कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगी। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस बिल के बहाने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल लाया गया है और इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में रही है। उन्होंने याद दिलाया कि महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक सबसे पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके अलावा राजीव गांधी के समय 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के जरिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और कार्यकताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर विस्तार से विचार किया गया और पंचायत चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। रजनी पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस में एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो नेता सरकार में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे संगठन का पद नहीं रखेंगे और जो संगठन में काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार में पद नहीं मिलेगा। इससे नए कार्यकताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा और संगठन में जवाबदेही भी तय होगी।

टीएमसी ने बंगाल को बनाया लूटपाट और घुसपैठ का अड्डा : अनुराग सिंह ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बंगाल विधानसभा चुनावों के अंतर्गत कोलकाता में माली (मालाकार) समुदाय को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित कर उनसे संवाद किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे माली भाई दिन के चौबीस घंटे, सप्ताह के सातों दिन और साल के बारहों महीने पिच से लेकर टर्फ और पूरे मैदान को तैयार करने व उसकी देखभाल में जुटे रहते हैं। दुनिया और दर्शक जो हरे-भरे सुंदर क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान देखते हैं, वह उनकी मेहनत का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतते हैं, वह भी उनकी मेहनत से ही संभव हो पाता है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद माली समाज की बेहतरी के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मंदिरों के बाहर फूल और माला बेचकर आजीविका चलाने वाले मालाकार भाई-बहनों से टीएमसी के लोग रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन यह सब जल्द समाप्त होगा। बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और भाजपा सरकार आने वाली है। सरकार बनने पर बंद पड़ी भर्तियां शुरू की जाएंगी, नए खेल स्टेडियम बनाकर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बंगाल में माओवाद और तुष्टिकरण बढ़ा। बामपंथी सरकार के समय बचे-खुचे उद्योग धंधे भी तबाह हो गए और गुंडा तंत्र स्थापित हुआ। ममता बनर्जी की सरकार में क्राइम, करप्शन, गुंडाराज, माफियाराज, स्मगलिंग, कटमनी और रंगदारी का बोलबाला हो गया। इन तीनों दलों ने मिलकर पश्चिम बंगाल को लूटपाट और घुसपैठ का अड्डा बना दिया। जिस कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टीएमसी माँ, माटी, मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन माँ को ममता ने हड़प लिया, माटी को माफिया ने निगल लिया और मानुष को मनी पावर ने कुचल दिया। आज यह सरकार ममता-माफिया-मनी पावर की सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में हिन्दू सुरक्षित नहीं हैं, मंदिर सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, न्याय व्यवस्था तक सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि पशु भी सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल को विकास का सपना दिखाकर सत्ता में आई सरकार ने पिछले 15 वर्षों में राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। पश्चिम बंगाल पर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है और यह देश में कर्ज के मामले में शीर्ष पर है।

नाहन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भगवान खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा से शाम मय हुआ शहर

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

नाहन शहर वीरवार को भगवान खाटू श्याम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्री बालाजी एवं खाटू श्याम शहर मंडल की ओर से आयोजित वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काली स्थान तालाब स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया।

शोभा यात्रा का शुभारंभ काली स्थान तालाब से विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। फूलों से सजे बाबा के भव्य रथ के साथ श्रद्धालु नाचते-गाते और हाथों में निशान (झंडे) लिए चल रहे थे। यह यात्रा नया बाजार, दिल्ली गेट, गोविंदगढ़, बाल्मीकि नगर, कच्चा टैंक, छोटा चौक, बड़ा चौक और गुन्नू घाट होते हुए शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी। जगह-जगह स्थानीय लोगों द्वारा पुष्प वर्षा और जलपान की व्यवस्था कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। देर शाम यह यात्रा ऐतिहासिक चौगान मैदान में पहुंचकर संपन्न होगी, जहाँ बाबा की विशेष आरती की जाएगी। आयोजक दीपक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा के बाद शुक्रवार को शाम चौगान मैदान में एक विशाल संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक संध्या में दिल्ली की प्रसिद्ध भजन गायिका भावना स्वर्णांजलि अपनी मधुर वाणी से बाबा का गुणगान करेंगी। संकीर्तन के लिए चौगान मैदान में भव्य दरबार सजाया जा रहा है। दीपक चौधरी ने बताया कि इस पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सुख-शांति, आपसी भाईचारे और सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना है।

एसएसपी सांबा ने बारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन का किया दौरा कामकाज की समीक्षा की

सांबा। सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुज कुमार आईपीएस ने आज बारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन का दौरा कर उसके समग्र कामकाज की समीक्षा की। उनके साथ सांबा के अतिरिक्त एसपी और बारी ब्राह्मणा के एसडीपीओ भी थे। दौरे के दौरान एसएसपी सांबा ने बारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारियों और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ विस्तृत बातचीत की और कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की रोकथाम और पता लगाने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रभावी पुलिसिंग और बेहतर सामुदायिक सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने, प्रमुख चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और बीट बुक के सख्त रखरखाव पर भी जोर दिया। पुलिस स्टेशन के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई जिसमें लंबित मामलों की समयबद्ध जांच और निपटान के साथ-साथ आधुनिक पुलिसिंग पद्धतियों के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

डॉ आंबेडकर ने समाज में जड़ हो चुकी व्यवस्थाओं को बदलने का किया प्रयास : डॉ. किस्मत कुमार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

भारतीय समाज की सुंदरता इसकी गतिशीलता है। यह समाज जड़ न होकर स्वयं को सदैव युगानुकूल अपडेट करता रहता है। भारत की इसी परंपरा के अनुरूप डॉ. आम्बेडकर ने समाज में जड़ हो चुकी व्यवस्थाओं को युगानुकूल बदलने के प्रयास अपने समय में किए। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर में डॉ. आम्बेडकर के चिंतन में भारतीय समाज विषय पर आयोजित व्याख्यान में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करते हुए विश्वविद्यालय के आम्बेडकर अध्ययन केंद्र के सहायक आचार्य डॉ. किस्मत कुमार ने यह उद्गार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में डॉ. आम्बेडकर के चिंतन पर प्रकाश डालते हुए डॉ. किस्मत कुमार ने कहा कि महापुरुषों के कार्यों का मूल्यांकन तात्कालिक समय में करना बहुत कठिन होता है। इसी कड़ी में डॉ. आम्बेडकर के कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि जन्म के 136 वर्ष बाद भी वे और उनके द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि समाज की पहचान और अध्ययन छोटी-मोटी बीमारियों के आधार पर नहीं बल्कि परंपराओं के आधार पर होता है। डॉ. आम्बेडकर का संपूर्ण जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन भी भारत की परंपराओं की पृष्ठभूमि पर ही होना चाहिए। महिला अधिकारों को दी संवैधानिक सुरक्षा : प्रो. प्रदीप कुमार अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अधिष्ठाता आकादमिक प्रो. प्रदीप कुमार ने महिला सशक्तिकरण में डॉ. आम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामाजिक एकात्मता के अलावा महिला उत्थान में भी डॉ. आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। उनके द्वारा बनाए हिन्दू कोड बिल में महिलाओं को बराबरी के अधिकार और उनके द्वारा दिए गए संविधान में महिलाओं को जो बराबर वोट का अधिकार दिया गया, वो अपने आप को विकसित और आधुनिक कहने वाले देशों से बहुत पहले दिया गया। उन्होंने कहा कि आज भारत की संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास करने की चर्चा हो रही है, उसके पीछे भी प्रेरणा शक्ति डॉ. आम्बेडकर ही हैं।

संक्षिप्त-समाचार

यज्ञ केवल आहुति नहीं, सेवा और सद्कर्मों का समन्वयः स्वामी राम स्वरूप

कठुआ। वेद मंदिर योल कैंप में 12 अप्रैल से आरंभ हुए 78 दिवसीय चारों वेदों के यज्ञानुष्ठान के दौरान स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य ने श्रद्धालुओं को यज्ञ की वास्तविक महिमा और महत्व समझाया। वेद मंत्रों की आहुतियों के साथ उनकी व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है बल्कि यह तीन महान शुभ कर्मों देवपूजा, संगतिकरण और दानकृपा समन्वय है। स्वामीजी ने कहा कि वेदों के अनुसार यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें देवपूजा के अंतर्गत माता-पिता, अतिथि, आचार्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा शामिल हो। केवल अग्नि में आहुतियां डालने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि सेवा और सद्कर्मों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने सामवेद और ऋग्वेद के मंत्रों का उल्लेख करते हुए बताया कि यज्ञ में आहुति वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ही दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में वेद ज्ञान से दूर होते हुए कई स्थानों पर यज्ञ की परंपरा को गलत रूप में अपनाया जा रहा है जो वेदों के सिद्धांतों के विपरीत है। स्वामी राम स्वरूप ने श्रद्धालुओं से आ'न किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदों की शिक्षाओं की ओर पुनः लौटना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ही समाज में सुख, शांति और भाईचारे जैसे सद्गुणों का विकास संभव है। यज्ञानुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर जीवन में अपनाने का संकल्प ले रहे हैं।

जब तक नशाखोरी की समस्या जड़ से खत्म नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगेः उपराज्यपाल

श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर से नशा मुक्ति नहीं हो जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने श्रीनगर मे महिला किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग सभी विभाग नशामुक्ति के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि मैंने 11 अप्रैल को जम्मू में 'नशा मुक्त' अभियान शुरू किया है और हमने तय किया है कि जब तक नशाखोरी की समस्या जड़ से खत्म नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया था तब जम्मू-कश्मीर में भी काफी प्रयास किए गए थे। पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, पहले से ज्यादा ड्रग्स जब्त हो रही हैं, पहले से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं और ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में कश्मीर में भी नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 3 मई को अभियान के कश्मीर चरण का शुभारंभ करेंगे। मैं आप सभी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आकर नशामुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए योगदान दें। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है या जिनकी बेटी नशे की शिकार हो गई है। हम इस बुराई से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब सरकार की शक्ति को जनता के प्रयासों का समर्थन मिले।

'ड्रग फ्री कैंपस' पर जीडीसी मढ़हीन में वाद-विवाद प्रतियोगिता, छात्रों ने दिया नशामुक्त भारत का संदेश

जम्मू-कश्मीर। देशव्यापी अभियान 'नशामुक्त भारत अभियान' के तहत 100 दिवसीय कार्यक्रम की शुरूआत को चिह्नित करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मढ़हीन में 'ड्रग फ्री कैंपस' विषय पर अंतर-कॉलेज वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस प्रतियोगिता में 10 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचारों व प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल के माध्यम से नशे जैसी गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज की प्राचार्य प्रो. (डॉ.) अनुपमा गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में किया गया। अपने संबोधन में प्राचार्य ने विद्यार्थियों को नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और इस नेक पहल में उनकी भागीदारी की सराहना की। प्रतियोगिता में समीक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि धीरज द्वितीय और नितिका तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतिभागियों का मूल्यांकन निर्णायक मंडलकृडॉ. मुनीषा देवी, डॉ. शालू रानी और प्रो. मनु सैनीकृद्वारा किया गया जिन्होंने छात्रों के तर्कों और प्रस्तुति कौशल की प्रशंसा की। कार्यक्रम का सफल समन्वय नशामुक्त भारत अभियान के कॉलेज संयोजक डॉ. बलबिंदर सिंह ने किया।

जम्मू में पहली बार श्री रघुनाथ मंदिर में महाशक्ति की भव्य आरती का आयोजन

जम्मू। मंदिरों के शहर जम्मू में पहली बार श्री रघुनाथ जी मंदिर में महाशक्ति की भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पहल श्री रघुनाथ जी की जम्मू आरती संस्था के तत्वावधान में की जा रही है, जिसका उद्देश्य डोगरा संस्कृति और प्राचीन धार्मिक पहचान को संरक्षित करना है। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और विशाल मंदिरों में शामिल श्री रघुनाथ जी मंदिर में 365 दुर्लभ मूर्तियां और 12 लाख शालिग्राम विराजमान हैं, जिन्हें भगवान नारायण के स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस सिद्धपीठ मंदिर की चार परिक्रमा करने से 33 करोड़ देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संस्था की चेयरपर्सन कुँवरानी डॉ. रितु सिंह और संस्थापक एवं उपाध्यक्ष बलदेव खुल्लर ने प्रेस वार्ता में बताया कि अक्षय तृतीया, 19 अप्रैल से प्रत्येक रविवार सायं 5:30 बजे जम्मू आरती का आयोजन किया जाएगा। इस पहल को धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग और डॉ. करण सिंह के आशीर्वाद के साथ शुरू किया गया है जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया था।

हिमाचल में जंगल राज का माहौल, बेटियां असुरक्षित और नशा माफिया बेखौफ : डॉ. सन्नी शुक्ला

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष डा सन्नी शुक्ला ने गुरूवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि देवभूमि में जंगल राज जैसा माहौल दिखाई देने लगा है। इस दौरान भाजयुमो के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी निशांत ठाकुर भी मौजूद रहे।

सनी शुक्ला ने मंडी जिले के सरकाघाट में 19 वर्षीय छात्रा की हत्या की घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बेटियां दिन-दहाड़े सुरक्षित न हों, वहां सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन), मैहतपुर, संसारपुर टैरेस, काला अंब और पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में नशा माफिया सक्रिय हो चुके हैं और युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर कार्रवाई न होने से लोगों में यह धारणा बन रही है कि नशा तस्करों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जिससे बड़ी मछलियां कानून की पकड़ से बाहर रह जाती हैं। सनी शुक्ला ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और भू-माफिया के बढ़ते प्रभाव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने चेस्टर हिल जमीन मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में भू-माफिया सक्रिय हैं और सरकार इन मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रशासनिक कैंप केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं और आम लोग, व्यापारी तथा उद्योगपति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि असुरक्षा का यह माहौल प्रदेश में निवेश को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो भाजयुमो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र जन-आंदोलन शुरू करेगा।

जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तारी

जम्मू। एसएसपी जम्मू के पर्यवेक्षण और एसपी सिटी साउथ, एसडीपीओ सिटी ईस्ट जम्मू और एसएचओ पीएस बाहु फोर्ट के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी और हेरोइन जैसे पदार्थ, नकदी की बरामदगी के साथ एक सफलता हासिल की। आईसी पुलिस पोस्ट नरवाल के नेतृत्व में और अन्य अधिकारियों की सहायता से पुलिस पोस्ट नरवाल की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल से ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग तस्कर की पहचान अंकुश पुत्र अनितेश निवासी राजीव नगर नरवाल जिला जम्मू के रूप में हुई। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 08 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ और 2900 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस स्टेशन बाहु फोर्ट जम्मू में एक मामला धारा 8/21/22/25/27 एनडी पीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 81/2026 दर्ज किया गया है और आरोपी को आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू पुलिस समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और नागरिकों से नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों के बारे में किसी भी जानकारी के लिए आगे आने का आग्रह करती है।

नारी सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम : डॉ. बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वीरवार को धर्मशाला में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने यह बात कही।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि अब महिलाओं के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण बदल चुका है। यह केवल महिला कल्याण नहीं, बल्कि महिला के माध्यम से समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीति निर्माण में संतुलन, संवेदनशीलता और व्यापक दृष्टिकोण आएगा। डॉ. बिंदल ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में महिलाओं के जीवन के हर चरण को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण 2.0, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी जैसी कई अन्य योजनाएं महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की आधारशिला है, जहां हर महिला सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का सपना साकार हो।

मंडी के सरकाघाट कांड में बिटिया के सवालों के जवाब दे सरकार : जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ मंडी जिला के सरकाघाट के गोपालपुर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बिटिया के माता-पिता और परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बिटिया की माता जी से मुलाकात की, उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। किसी की मां से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे गांव में मातम पसरा है। पूरा परिवार सदमे में है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना ने अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ दिए हैं। पिता और परिजन इसे सामान्य घटना मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि राह चलते किसी की अचानक हत्या करने का कोई तुक नहीं बनता। घटना के चार दिन बाद भी पुलिस किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। सरकार से निवेदन है कि परिजनों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाए। जांच में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज बिटिया हमारे साथ नहीं है। उसे न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलवाना ही बिटिया को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश का माहौल है।

मौसम | हिमाचल के शिमला की रातें मैदानों से भी गर्म

अगले 3 दिन ओलावृष्टि, आंधी व बिजली गिरने का अलर्ट जारी

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा, इसका असर 17 से 19 के बीच पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में आज रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर 17 से 19 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। खासतौर पर 17 अप्रैल को कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि इन चार जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला जिलों में इसी दिन तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 और 19 अप्रैल को भी कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। 20 अप्रैल को भी मौसम खराब रहेगा, जबकि 21 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद है इस बीच प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है। शिमला में बीती रात न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। खास बात यह रही कि शिमला का रात का तापमान मैदानी क्षेत्र ऊना (14 डिग्री) से भी अधिक रहा, जिससे शिमला की रातें मैदानों से भी गर्म महसूस की गईं। मनाली का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। प्रदेश में अन्य प्रमुख शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो केलांग 1.0, ताबो 3.4, कुकुमसेरी 4.2, कल्पा 5.8, सराहन 9.1, सेओबाग 9.7, कुफरी 9.8, सोलन 10.5, भुंतर 11.0, बरठीं 11.0, सुंदरनगर 12.8, ऊना 14.0, मंडी 14.2, बिलासपुर 14.5, पालमपुर 15.5, जुब्बड़हट्टी 15.5, कांगड़ा 15.7, नाहन 15.9, पांवटा साहिब 18.0 और देहरा गोपीपुर 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से 19 अप्रैल के बीच तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है, जबकि 19 अप्रैल के बाद फिर से तापमान बढ़ सकता है। उधर मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार केवल लाहौल-स्पीति जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जबकि हमीरपुर, किन्नौर और चंबा के कुछ हिस्सों में सामान्य वर्षा का अनुमान है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहने की आशंका है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा, स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन कर हरियाणा में की जनगणना प्रक्रिया की शुरूआत

कहा- जनगणना-2027 विकसित हरियाणा की आधारशिला, मुख्यमंत्री ने जनगणना को जन-आंदोलन बनाने का किया आह्वान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन (री'ा एल्लश्रीॄ३ङ्क्ल्ल) फॉर्म भर कर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने प्रदेशवासियों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने वीरवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल और समय की बचत करने वाली प्रणाली है। यह पहल प्रधानमंत्री के ईज ऑफ लिविंग और डिजिटल इंडिया के विजन को और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 विकसित हरियाणाझ्विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राज्य के समग्र और न्यायसंगत विकास की आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों को डिजिटली स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि सटीक और विश्वसनीय जनगणना आंकड़े ही ऐसी नीतियों और योजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र ह्यहमारी जनगणना, हमारा विकासह्ण को दोहराते हुए कहा कि यह संकल्प हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा।

उन्होंने कहा कि भारत में जनगणना का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी व्यवस्थित शुरूआत वर्ष 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद 6वीं जनगणना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े ही राज्य और देश की विकास योजनाओं की नींव होते हैं। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए योजनाओं के निर्माण तक हर नीति की आधारशिला सही जनगणना आंकड़े ही होते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार की सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाएं प्रभावी और न्यायसंगत बन सकें।

उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेगी। स्व-गणना सुविधा के तहत नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए री.ूल्ल२४२.ङ्क्ष्५.ल्ल पोर्टल विकसित किया गया है, जहां नागरिक मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित लॉगिन कर अपने राज्य, जिला और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिह्नित करेंगे और परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और गोपनीय बताया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय होती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी के साथ यह जानकारी साझा नहीं की जाती। नागरिकों की निजता और विश्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक स्व-गणना सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 1 मई से 30 मई के बीच जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें।

उन्होंने युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, पंचायत प्रतिनिधियों, नगर पार्षदों और समाज के जागरूक वर्गों से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर लोगों को जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रहे। उन्होंने जनगणना से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि जनगणना में हिस्सा लें और इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को मिलकर सफल बनाएं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त और जनगणना के लिए हरियाणा स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 2011 के बाद जनगणना हो रही है। इस बार की जनगणना की खास बात यह है कि इस बार डिजिटल रूप से जनगणना की जा रही है। 16 से 30 अप्रैल तक नागरिक पोर्टल पर जाकर स्व-गणना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना के लिए लगभग 60 हजार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, जनगणना करने वाले कर्मियों के लिए मानदेय भी बढ़ाया है।

निदेशक, जनगणना श्री ललित जैन ने कहा कि आज हरियाणा के 51000 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स को डिजिटलाइज कर दिया है और इनका सारा नजीर नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे राज्य के नागरिक आसानी से स्व गणना कर सकेंगे। यह सारा डेटाबेस हरियाणा के विकास के लिए सहायक होगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल जनगणना के लिए नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी बड़ी आसानी से स्व गणना कर सकता है। इस डिजिटल सेंसस से समय की बचत होगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती हेमा शर्मा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, अतिरिक्त निदेशक श्री मनीष लोहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सपनों को सच करने का माध्यम:कंवलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों को सच करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अधिनियम के लिए 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया है। यह अधिनियम महिलाओं को नए अवसर प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा, जब महिलाएं पूरी तरह सशक्त होंगीं। यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को गति देने वाला एक निर्णायक कदम है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगीं, तो विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी, संतुलित और टिकाऊ बनेगी। नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी ढांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया जिनके नेतृत्व में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर कई ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

'दूरसंचार विभाग, हरियाणा एलएसए द्वारा सिरसा, हरियाणा में सुरक्षित दूरसंचार प्रथाओं एवं साइबर धोखाधड़ी रोकथाम पर हितधारक कार्यशाला एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
सिरसा

दूरसंचार विभाग हरियाणा एलएसए ने सिरसा पुलिस के सहयोग से टैगोर ऑडिटोरियम, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में एक प्रभावी संवाद कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता श्री राधाचरण शाक्य, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार, हरियाणा एलएसए एवं श्री दीपक सहारण, पुलिस अधीक्षक सिरसा ने की। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता के अधिकारी तथा जिले भर के प्वाइंट्स ऑफ सेल शामिल थे। यह कार्यक्रम सुरक्षित दूरसंचार प्रथाओं को बढ़ावा देने एवं साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक, हरियाणा एलएसए ने राष्ट्र निर्माण एवं माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सुरक्षित संचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से बढ़ते साइबर धोखाधड़ी एवं ठगी के मामलों पर चिंता व्यक्त की और सभी हितधारकों द्वारा सतर्कता एवं सक्रिय उपाय अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाए गए विभिन्न तंत्रों की जानकारी दी, जिनमें अवैध गतिविधियों में संलिप्त मोबाइल नंबरों की पहचान एवं ट्रैकिंग हेतु सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तथा संचार साथी पोर्टल का उपयोग शामिल है। अतिरिक्त महानिदेशक ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र , राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सेवा केंद्रों के सहयोग से वित्तीय जोखिम संकेतक विकसित किए जा रहे हैं, जो दूरसंचार के दुरुपयोग से उत्पन्न संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान एवं चिन्हांकन में सहायक हैं। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग हेतु प्रमुख माध्यमों की जानकारी भी दी गई, जिनमें त्वरित रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन तथा पोर्टल शामिल हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप कर वित्तीय नुकसान से बचाव किया जा सकता है। प्रतिभागियों को सुरक्षित बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन के लिए 1600 श्रृंखला के उपयोग के बारे में भी अवगत कराया गया तथा दूरसंचार सेवाओं के जिम्मेदार उपयोग एवं सतर्कता के महत्व पर जोर दिया गया। चर्चा के दौरान एसपी सिरसा ने नागरिकों की साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु पहल की सराहना की तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कॉल्स, वर्चुअल कॉल्स एवं वीपीएन के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। आश्वासन दिया कि इन मुद्दों का समाधान विधि के प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण क्षमता एवं समन्वय के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसमें संचालकों एवं पुलिस अधिकारियों के प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया गया।

संक्षिप्त-समाचार

कुरुक्षेत्र समिति की बैठक आयोजित, बैठक में विभिन्न योजनाओं पर हुआ मंथन

कुरुक्षेत्र। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से श्री कृष्ण कृपा समिति व जीओ गीता कुरुक्षेत्र की बैठक दिनांक गीता ज्ञान संस्थानम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में 20 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली गीता सम्मान यात्रा की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई तथा इसके सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों के गठन एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। इसके साथ ही मासिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रकल्पों को नियमित रूप से संचालित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान गीता पाठ, सत्संग, युवा जागरूकता कार्यक्रम, महिला सहभागिता, तथा समाज में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पुरुषोत्तम मास के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित करने तथा अधिक से अधिक लोगों को गीता से जोडने के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त संगठन विस्तार, कार्यकताओं के प्रशिक्षण, तथा विभिन्न नगरों में गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा समिति के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु विचार साझा किए। बैठक के अंत में प्रधान डॉ. ऋषिपाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर स्वामी जी के मार्गदर्शन अनुसार समाज में गीता के संदेश का व्यापक प्रसार करना है। बैठक संगठन की आगामी योजनाओं को गति देने एवं सामाजिक-आध्यात्मिक गतिविधियों को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

हरियाणा में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तुरन्त प्रभाव से दो आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार महेंद्रगढ़ (नारनौल) के उपायुक्त श्री मनोज कुमार-कको वित्त विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), फरीदाबाद की प्रशासक तथा शहरी संपदा, फरीदाबाद की अतिरिक्त निदेशक सुश्री अनुपमा अंजलि को महेंद्रगढ़ (नारनौल) का उपायुक्त लगाया गया है।

हमारी जनगणना, हमारा विकास – मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरूआत की

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्व–गणना प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए कहा कि जनगणना एक निश्चित अवधि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका डाटा पूरी तरह सरल, सुरक्षित और गोपनीय होता है। यह डाटा विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाने तथा भविष्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री आज स्व–गणना करने के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 का शीर्ष वाक्य हमारी जनगणना, हमारा विकास है, जो इस अभियान के महत्व को दशार्ता है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना और परिसीमन दो अलग-अलग विषय हैं। परिसीमन का कार्य लंबी अवधि के बाद किया जाता है और यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सार्वजनिक महत्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में भी जनगणना का डाटा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इसमें सार्थक सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्व–गणना की प्रक्रिया आज से 30 अप्रैल, 2026 तक चलेगी, जबकि 1 मई से 30 मई तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सफल बनाने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार: कृष्ण लाल पंवार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

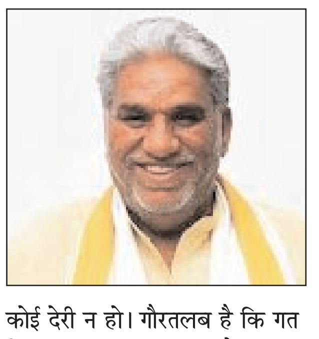

- आग से प्रभावित किसानों को मिलेगा शीघ्र मुआवजा
- हरियाणा सरकार किसानों के हित में निरंतर कर रही कार्य

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पानीपत के बुआना लाखु गांव में हुई आगजनी की घटना में जिन किसानों की फसलें जलकर नष्ट हो गई हैं, उन्हें सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने वीरवार को पानीपत में प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का सही आकलन कर प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने में कोई देरी न हो। गौरतलब है कि गत दिवस बुआना लाखु गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग में करीब 32 किसानों की लगभग 80 एकड़ में खड़ी गेहूं की तैयार फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस घटना ने किसानों को आर्थिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया है। प्रशासन द्वारा मामले की दो बार जांच भी की जा चुकी है, ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका के महत्व को भली-भांति समझती है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ सीधे किसानों तक पहुंच रहा है।

इस मौके पर मंत्री ने किसानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह नुकसान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और उम्मीदों का भी है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके दुख में साझेदार है और हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी।

आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें आरक्षित करना है अनिवार्य : शिक्षा मंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ृ) के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को कक्षा प्रथम एवं उससे पूर्व की कक्षाओं में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी विद्यालय अपनी आरक्षित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट एवं उज्ज्वल पोर्टल पर 11 मार्च से 20 मार्च 2026 तक अपलोड करें।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल 9230 निजी विद्यालयों में से 8621 विद्यालयों ने समय रहते पोर्टल पर सीटें घोषित कीं, जबकि 609 विद्यालयों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त सीटें घोषित करने वाले 8621 विद्यालयों में से 891 विद्यालय ऐसे पाए गए, जिन्होंने अपनी मान्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। इसी कारन उनकी प्रविष्टियां अस्वीकृत कर दी गईं हैं। इस लापरवाही के कारण विभाग द्वारा लगभग 1500 विद्यालयों का एमआईएस पोर्टल अस्थायी रूप से बंद किया गया।

शिक्षा मंत्री श्री ढांडा ने कहा कि इस विषय को लेकर निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने उनसे भेंट कर अवगत कराया कि सत्र 2026-27 की दाखिला प्रक्रिया जारी है, लेकिन एमआईएस पोर्टल बंद होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने बच्चों और अभिभावकों के हित को सर्वोपरि मानते हुए एक संवेदनशील निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिन विद्यालयों का एमआईएस पोर्टल सीटें घोषित न करने या दस्तावेज अपलोड न करने के कारण बंद किया गया था, उन्हें अब पुनः खोलते हुए एक और अवसर प्रदान किया गया है। संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्रता से अपनी मान्यता से संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें तथा आटीई अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी निजी विद्यालयों को अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना होगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी पात्र बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहना पड़े।

भाजपा परिसीमन के जरिए सत्ता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
नई दिल्ली / चंडीगढ़

- महिला आरक्षण व जाति जनगणना पर भाजपा पर निशाना
- लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की दिशा में एक चिंताजनक कदम है

सिरसा की सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने महिला आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता पहले ही स्पष्ट कर चुकी है और वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को देश का संवैधानिक संकल्प मानते हुए उसका पूर्ण समर्थन करती है। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन प्रक्रिया के जरिए सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है, जो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की दिशा में एक चिंताजनक कदम है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को नजरअंदाज कर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने का भी उल्लेख किया। कांग्रेस की नीति का जिक्र करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में वास्तविक समानता तभी संभव है जब सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भाजपा सरकार से अपील की कि वह भ्रम फैलाना बंद करे और दलित, ओबीसी, तथा आदिवासी समुदायों के अधिकारों से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे।

नगर निगम पंचकूला व अंबाला चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण की अध्यक्षता में आज नगर निगम पंचकूला एवं अंबाला के आम चुनावों की तैयारियों को लेकर पंचकूला में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव सामग्री, कानून व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, मतदान कर्मियों की तैनाती, प्रशिक्षण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं तथा दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं सहित सभी प्रबंध समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाएं।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न न हो। श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं किया जाएगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की नई योजना- परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन नहीं किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगर निगम पंचकूला की वार्डवार अंतिम मतदाता सूची 27 मार्च 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है। नियमों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम जारी होने से नामांकन की अंतिम तिथि तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने का अधिकार रहेगा। केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम संबंधित वार्ड में जोड़े जा सकेंगे,

जिनका नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन नगर निगम की वार्डवार सूची में शामिल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संभावित प्रत्याशी का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में विधिवत शामिल है तो उसे नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की तुरंत पहचान कर वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। श्री देवेंद्र कल्याण ने कहा कि मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध रहे। उन्होंने पुलिस विभाग को असामाजिक तत्वों, अवैध शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों एवं आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। मतदान दिवस से पहले विशेष अभियान चलाने, नाकों और गश्त बढ़ाने तथा मतदान केंद्रों के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। जिन मतदान केंद्रों अथवा संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकता हो, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में 09 मई से 13 मई 2026 तक बिजली और पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर बल दिया गया। श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक मतदान दल को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने तथा मतदान दिवस पर मतदाताओं के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने, स्पष्ट संकेतक लगाने तथा एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयंसेवकों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए।

श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने विशेष रूप से कहा कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता एवं अस्वस्थ मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान सुविधा दी जाए। सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर, रैंप, शेड, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि वोटर स्लिप 7 मई तक प्रत्येक घर तक पहुंचाकर वितरित की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्लिप्स थोक में न दी जाएं, बल्कि घर-घर जाकर व्यवस्थित रूप से वितरण किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और अन्य शैक्षणिक भवनों में मतदान केंद्र या मतगणना केंद्र स्थापित किए जाने हैं, वहां भवनों की मरम्मत, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल तथा पहुंच मार्गों की स्थिति तुरंत दुरुस्त कराई जाए।

संपादकीय

महिला आरक्षण बिल पर बवाल: जनगणना बनाम परिसीमन, संसद में गरमा गई बहस

भारतीय संसद का विशेष सत्र जब भी बुलाया जाता है, तो उसके साथ एक राजनीतिक गर्माहट स्वाभाविक रूप से आती है। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार ने जब महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 को एक साथ पेश करने की कोशिश की, तो सदन के भीतर तीखी नोकझोंक का माहौल बन गया। एक तरफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच जो वाद-विवाद हुआ, वह केवल दो नेताओं की तकरार नहीं था – वह भारत की आरक्षण नीति, जनगणना की जरूरत और संविधानिक मयार्दाओं को लेकर एक व्यापक और जरूरी राष्ट्रीय बहस का प्रतिबिंब था। अखिलेश यादव ने सदन में सवाल उठाया कि आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? उनका तर्क सीधा था – पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद जाति जनगणना, और तब जाकर आरक्षण का प्रश्न तार्किक रूप से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण की समर्थक है, लेकिन उसे परिसीमन के रास्ते लागू करने के तरीके से वह सहमत नहीं। उनके इस वक्तव्य में राजनीतिक सतर्कता थी – एक ओर महिलाओं के प्रति समर्थन दशार्ना और दूसरी ओर सरकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना। उनका आरोप था कि सरकार जनता के साथ छल कर रही है, क्योंकि जनगणना पूरी हुए बिना परिसीमन करना न केवल अधूरा है, बल्कि संभावित रूप से भ्रामक भी है। इसके जवाब में अमित शाह ने जो कहा, वह सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार जाति जनगणना भी उसी के साथ कराई जाएगी। लेकिन उनकी सबसे तीखी और महत्वपूर्ण टिप्पणी तब आई, जब उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की माँग को असंवैधानिक करार दिया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की माँग उठाए जाने पर शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा – धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। शाह का यह कथन संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की अनुमति देता है – न कि किसी धार्मिक पहचान के आधार पर। इसलिए यदि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटे की माँग धार्मिक आधार पर है, तो वह संविधानसम्मत नहीं है। हाँ, यदि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, तो उनकी गणना ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग में की जा सकती है – धर्म के आधार पर नहीं। परंतु इस पूरी बहस में एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता – और वह है जनगणना और परिसीमन का आपसी संबंध। विपक्ष का तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना अव्यावहारिक और अपूर्ण होगा। पंद्रह वर्ष पुराने आँकड़े देश की वास्तविक जनसंख्या को नहीं दशार्ते। इस बीच जनसंख्या का वितरण बदला है, शहरीकरण हुआ है, और कई राज्यों की जनसंख्या में भारी फेरबदल आया है। ऐसे में यदि परिसीमन 2011 के आधार पर हो और उसके बाद महिला आरक्षण लागू हो, तो क्या यह वास्तव में न्यायसंगत होगा? कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने इसे और आगे ले जाते हुए कहा कि परिसीमन विधेयक देश की संघीय संरचना पर सीधा हमला है। दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से ही यह डर व्याप्त है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को परिसीमन में नुकसान होगा और उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। यह चिंता केवल राजनीतिक नहीं है – इसमें एक संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न भी है। सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। यह आश्वासन राहत देने वाला है, लेकिन जब तक पारदर्शी आँकड़े और स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आती, संदेह बना रहेगा। राजनीति में विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस प्रक्रिया और पारदर्शिता से बनता है। इस पूरे विवाद को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा जितना सामाजिक न्याय का है, उतना ही राजनीतिक भी। हर दल महिलाओं के समर्थन का दावा करता है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो आपत्तियाँ उठने लगती हैं। समाजवादी पार्टी जनगणना की माँग कर रही है – यह माँग तार्किक है, पर इसे लेकर तात्कालिकता की कमी पहले भी दिखती रही है। सरकार परिसीमन के साथ आरक्षण लागू करना चाहती है – यह इरादा सराहनीय है, पर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता जरूरी है। अंत में यह कहना उचित होगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की माँग न केवल असंवैधानिक है, बल्कि वह उस बुनियाद को कमजोर करती है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है। आरक्षण का उद्देश्य सदियों से चले सामाजिक अन्याय को दूर करना है, धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाना नहीं। जनगणना जल्द होनी चाहिए, जाति की वास्तविक गणना होनी चाहिए, और उसके बाद एक न्यायसंगत तथा संवैधानिक ढाँचे के भीतर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो देश को बाँटेगा नहीं, बल्कि जोड़ेगा।

बीबीएन प्रदूषण की मार झेलने को अभिशप्त

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाने वाला बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र बहुत से नकारात्मक कारणों से भी चर्चा में रहता आया है। वर्तमान में यह क्षेत्र प्लास्दा में किण्वन उद्योग लिमिटेड के एपीआई (सक्रिय भेषजीय सामग्री) संयंत्र के कारण चर्चा में है। इस प्लांट के कारण आसपास के 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में जनता का दुर्गन्ध के कारण सांस लेना दूभर हो गया है और प्लांट का प्रदूषित जल नदी-नालों में छोड़ने के कारण जल भी प्रदूषित हो गया है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण आसपास के क्षेत्रों में हैंडपंप सूखने लग पड़े हैं। इस संयंत्र को प्रतिदिन 6.7 किलो लीटर पानी उपयोग की स्वीकृति है। लोगों का कहना है कि यह संयंत्र काफी ज्यादा भूजल दोहन कर रहा है, जिसके कारण पहले से लगे हैंडपंप सूखने लगे हैं।

संयंत्र के दुष्प्रभावों को बारीकी से समझने से पहले बीबीएन की ऐतिहासिक लापरवाह संस्कृति पर नजर डाल लेते हैं। 2025 तक कार्यरत 2919 इकाइयों में से 87 पर्यावर्णीय प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी प्रावधानों का उलंघन करते हुए पकड़ी गईं और उनसे 3.2 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वसूला। 27 इकाइयों और चार स्टोन क्रशरों की बिजली काटी गई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए गए उपकरणों का समय-समय पर सुधार करना पड़ता है, जो नहीं किया गया और सामयिक रखरखाव के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नवीकरण करवाना पड़ता है, जो नहीं करवाया गया।

बीबीएन में 308 इकाइयां लाल श्रेणी की हैं, जिनमें ये उल्लंघन ज्यादा पाए गए। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सुधार या रखरखाव पैसा बचाने के लिए ही ये लोग नहीं करते हैं और इससे कई बार भ्रष्टाचार भी जुड़ा रहता है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के एक अध्ययन में यह सामने आया की भूजल में सल्फेट, तांबा, लोहा, स्वीकृत स्तर से ज्यदा पाया गया। अम्लीयता भी अधिक पाई गई। वायु सूचकांक खतरनाक स्तर 324 मापा गया। जाहिर है कि जहां उद्योग विकास के लिए लगाये जाते हैं वहां औद्योगिक प्रदूषण को व्यापारिक हितों को मुख्यता देने वाले उद्योगपति, कोई महत्व नहीं देते हैं और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में घोर लापरवाही बरतते हैं। इससे एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति बन जाति है।

उद्योग न लगाएं तो बेरोजगारी और लगाएं तो प्रदूषण जनित लापरवाहियों से जीवन दुखी और असंभव। इसलिए हिमालय को प्रदूषणकारी लाल श्रेणी की औद्योगिक गतिविधियों से दूर रखने की हिमालय नीति अभियान और सहयोगी सामाजिक जन आन्दोलन की वकालत करते रहे हैं ताकि यह क्षेत्र पर्यटन और मैदानी प्रदूषण से थके हारे लोगों के लिए सामयिक विश्राम स्थल के रूप में बचा रहे। अगर हिमालय भी धूल, धुएं और अशुद्ध जल का घर बन जाएगा तो मानवता को विश्रांति कहां मिलेगी। सवाल है कि देश के लिए हिमालय द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं को होने वाली अपूरणीय हानि की भरपाई कैसे होगी। स्थानीय समुदायों को प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य, आजीविका और असुविधा का गुनहगार कौन होगा। ये सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं।

अब सक्रिय भेषज सामग्री को समझने का प्रयास करते हैं। ये वह सामग्रियां हैं जो किसी दवाई में वांछित असर या गुण प्रदान करती हैं। ये रोगी को देने के लिए तैयार दवाई का लगभग आधा हिस्सा हैं और दूसरा आधा है एक्ससेपिएंट्स या सहायक तत्व। ये रासायनिक स्तर पर निष्क्रिय होते हैं, जबकि इनसे मिल कर रासायनिक तौर पर सक्रिय भेषज सामग्रियां या घटक ही दवाई को वांछित गुण प्रदान करती हैं। इन सक्रिय भेषज सामग्रियों को बनाने की प्रक्रिया भी काफी पेचीदा होती है जिसमें अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है, जिससे इन रसायनों से प्रदूषण फैलने का भी खतरा बना रहता है। अतः रसायन मार्ग आधारित सक्रिय भेषज घटकों के निर्माण के बजाय अब कई दवा कंपनियां बैक्टिरिया या खमीर आधारित किण्वन मार्ग को अधिमान दे रही हैं।

इसमें विभिन्न भेषजीय तत्वों को विभिन्न सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से उपचारित करके किण्वन (खमीरीकरण) से विभिन्न रासायनिक यौगिक प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिन्हें एपीआई या सक्रिय भेषजीय घटक कहा जाता है। यह तो ठीक है कि रासायनिक मार्ग के मुकाबले किण्वन (खमीरीकरण) मार्ग से कम प्रदूषण होता है किन्तु यह मार्ग भी कदाचित निरापद नहीं है। खमीरीकरण में दुर्गन्ध पैदा होती है जिसका सही उपचार न किया जाए तो आसपास के निवासियों का जीना दूभर हो जाता है। इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में अपशिष्ट पैदा होता है, जिसके निपटान के लिए निर्धारित मानदंडों का प्रयोग न करके अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगा कर भी उनको पैसा बचाने के लिए संचालित ही नहीं किया जाता। आक्सीकरण द्वारा अपघटनीय और केवल जैवीय रूप से अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ भी बिना यह तय किए कि इनके अपघटन के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाएगी, बिना संशोधित किए ही खुले छोड़ दिए जाते हैं, जो एपीआई एकत्रित करने योग्य नहीं बचते और एंटीबायोटिक अपशिष्ट भी बिना संशोधित किए जल, और मिटटी प्रदूषण द्वारा पर्यावरण और मानव एवं अन्य पशु जगत के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के नाम पर बहुत सी जानकारियों को छुपाया जाता है इसके कारण अपशिष्ट प्रबन्धन पर निगरानी रखना कठिन हो जाता है। इन सबका एकत्रित विषाक्त प्रभाव कितना पड़ रहा है, इसका अभी तक पूर्ण आकलन ही नहीं किया गया है। अतः ठोस और तरल या अर्ध तरल अपशिष्ट पदार्थों का संशोधन, उनके खतरनाक विषाक्त स्तर के आकलन के अनुसार कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिए वरना यह लापरवाही पर्यावरण, मानव और जीव स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। एक सदइच्छा से किया गया प्रयास स्थानीय समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। अतः उद्योगपतियों को तमाम सुविधाएं देने के बाद भी उनकी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

(लेखक, हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष और पर्यावरणविद् हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज कार्यक्षेत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है। प्रेम जीवन में हल्की तकरार की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद में संयम रखें। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः मानसिक दबाव आज बढ़ सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होगी। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य को परेशानी हो सकती है। एकाग्रता की कमी के कारण आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खानपान और नींद का विशेष ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः आय के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों में भी इजाफा संभव है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः आज कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर यदि वजन बढ़ा हुआ है। आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ हल्की नोकझोंक संभव है। भारी और तली-भुनी चीजों से दूरी बनाना बेहतर रहेगा, वरना पेट और कमर से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः नई तकनीकों और आधुनिक विचारों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। घर में मन कम लगेगा और कहीं बाहर जाने या यात्रा का विचार बन सकता है। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता न करें। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा, जिससे काम में मन लगेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में बच्चों का व्यवहार अनुशासित रहेगा, जिससे संतोष मिलेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात के योग हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क बढ़ेगा, हालांकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। पिता के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी या अति-उत्साह में निर्णय लेने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और पारिवारिक तनाव कम होगा। हालांकि मन में किसी अज्ञात कारण से चिंता बनी रह सकती है। करियर को लेकर आप पूरी तरह केंद्रित रहेंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। नई नौकरी के अवसर भी सामने आ सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मकरः प्रेम जीवन में नई शुरूआत हो सकती है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। आपकी प्रतिभा और कार्यक्षमता की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता और समझदारी बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सोच-समझकर बयान देना चाहिए। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन बढ़ते खर्च थोड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

मीनः रुके हुए कार्यों में फिर से गति आएगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें। शारीरिक थकान या दर्द महसूस हो सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

भारत का फार्मा सेक्टर : नवाचार और युवाओं के लिए नया आकाश

अनुप्रिया पटेल

भारत आज दुनिया की 'फामेर्सी' के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप अब हम केवल जेनेरिक दवा बनाने वाले देश से आगे बढ़कर एक 'नवाचार-आधारित' वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां बनाना है जिससे देश के हर नागरिक कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं से मिल सकें। साथ ही सरकार निरंतर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है और भारतीय फार्मा उद्योग को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम कर रही है।

भारत की अब तक की सफलता उसकी उत्पादन क्षमता, लागत दक्षता और गुणवत्ता मानकों पर आधारित रही है। विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं और 60 प्रतिशत वैक्सीन आपूर्ति के साथ देश ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 8 से 10 वर्षों में देश को उच्च-मूल्य, नवाचार-आधारित बायोफार्मा और उन्नत चिकित्सीय उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।

इसकी आधारशिला के रूप में हालिया केंद्रीय बजट में घोषित ₹10,000 करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार आधारित उद्योगों और अगली पीढ़ी की दवाओं के विकास को गति प्रदान करेगा।

आर्थिक आंकड़े भी इस बात को दशार्ते हैं कि भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग वर्तमान में 50 अरब डॉलर का है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2030 तक इसके 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इसे केवल संख्या नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के रोडमैप के तौर पर भी देखने की जरूरत है।

वर्तमान में फार्मास्युटिकल उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। 2030 तक हेल्थकेयर और फार्मा क्षेत्र में 20 से 25 लाख नए रोजगार सृजित होंने की उम्मीद है। बायोफार्मा, मेडटेक और क्लीनिकल रिसर्च जैसे उभरते क्षेत्रों ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।

हमारी सरकार का मानना है कि युवाओं की सफलता की नींव एक मजबूत शैक्षणिक ढांचे पर टिकी होती है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर के लिए और भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश में तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, वर्तमान में कार्यरत सात नाईपर संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन सात संस्थानों में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की गई है, जो अनुसंधान और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाईपर मोहाली में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल दवाओं की खोज एवं विकास, नाईपर अहमदाबाद में मेडिकल डिवाइसेज, नाईपर हैदराबाद में बल्क ड्रग्स, नाईपर कोलकाता में फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नाईपर रायबरेली में नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाईपर गुवाहाटी में फाइटोफार्मास्यूटिकल्स तथा नाईपर हाजीपुर में बायोलॉजिकल थेरैप्यूटिक्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों का सीधा लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। नाईपर केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे ऐसे केंद्र बनेंगे जहां छात्र उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर काम करेंगे। इससे हमारे छात्र केवल 'जॉब सीकर' नहीं बल्कि 'जॉब क्रिएटर' और नवाचारी बनेंगे।

बदलते दौर में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक फार्मा सेक्टर के लगभग 30-35 प्रतिशत कार्यबल को री-स्किलिंग यानी नए कौशल सीखने की जरूरत होगी। केयर डिलीवरी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषाएं बदल रही हैं। डेटा विश्लेषण, डिजिटल हेल्थ और नियामक मामलों में उच्च कौशल वाले युवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। हमारी सरकार का ध्यान इसी 'स्किल गैप' को भरने पर है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र क्लीनिकल रिसर्च और अनुसंधान और विकास में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करें।

शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करना हमारी प्राथमिकता है। जब तक हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतें एक समान नहीं होंगी, तब तक हम 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसीलिए, हम 'उद्योग-अकादमिक साझेदारी' को मजबूत कर रहे हैं। इसी दिशा में, शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल बिठाने के लिए नाईपर और उद्योग के बीच 356 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिशनों के माध्यम से छात्रों को सीधे कंपनियों के साथ जुड़ने के मौके दिए जा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनेगा।

औषधि क्षेत्र का विकास जीडीपी बढ़ाने के साथ-साथ देश के युवाओं को सशक्त बनाने का भी एक मिशन है। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नींव हमारे युवा वैज्ञानिकों, शोधकताओं और पेशेवरों के कंधों पर है। नाईपर का विस्तार और बजट में किए गए प्रावधान इस बात का प्रमाण हैं। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां एक छात्र अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वैश्विक स्तर पर बदलाव ला सके। भारत के औषधि क्षेत्र का यह स्वर्णिम युग हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है।

लेखक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

शैक्षणिक अनुसंधान मानकों में गिरावट: वैश्विक शैक्षणिक समुदाय के लिए चुनौतियाँ और परिणाम

डॉ. अमन कुमार भारद्वाज
एसोसिएट प्रोफेसर
एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय

डॉ. शिखा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर
एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय

उच्च गुणवत्ता वाला अनुसंधान समाज की समस्याओं के समाधान, आर्थिक विकास और बौद्धिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान वैज्ञानिक, तकनीकी और नीतिगत विकास में योगदान देता है। विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ज्ञान के उत्पादन और प्रसार के प्रमुख केंद्र होते हैं। समकालीन समाज में शैक्षणिक अनुसंधान को ज्ञान निर्माण और नवाचार की रीढ़ माना जाता है। शैक्षणिक सम्मेलन हमेशा से विद्वानों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सम्मेलन शोधकताओं को अपने नए निष्कर्ष साझा करने, विशेषज्ञों से रचनात्मक सुझाव प्राप्त करने और पेशेवर नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये सम्मेलन पीएचडी शोधार्थियों और युवा विद्वानों को वरिष्ठ विशेषज्ञों से सीखने और नवीनतम विकास को समझने का अवसर भी देते हैं।

वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में सम्मेलनों, जर्नलों और शोध पत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि यह जानकारी के प्रसार में सहायक है, लेकिन इसके साथ ही अनुसंधान गुणवत्ता में गिरावट और अनैतिक शैक्षणिक गतिविधियों की समस्या भी बढ़ रही है। विशेष रूप से, शैक्षणिक सम्मेलनों के व्यावसायीकरण और शिकारी प्रकाशनों के बढ़ने से शैक्षणिक मानकों में गिरावट आई है। आजकल कई शैक्षणिक सम्मेलन गुणवत्ता बनाए रखने की बजाय राजस्व उत्पन्न करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। कुछ सम्मेलन त्वरित प्रकाशन का वादा करते हैं और बिना उचित समीक्षात्मक प्रक्रिया के शोध पत्र स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति 'प्रकाशित करो या समाप्त हो जाओ' संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिससे शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

इस निबंध का मुख्य उद्देश्य उन कारकों पर चर्चा करना है जो शैक्षणिक सम्मेलनों और अनुसंधान की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनते हैं, साथ ही इसके वैश्विक प्रभाव और सुधार के उपायों को प्रस्तुत करना है।

अनुसंधान गुणवत्ता में गिरावट के कारण

वर्तमान साहित्य में शिकारी प्रकाशनों के बढ़ते प्रभाव को विस्तार से बताया गया है। एक प्रमुख कारण यह है कि विद्वानों पर अधिक संख्या में शोध पत्र प्रकाशित करने का दबाव बढ़ गया है। आज की पुरस्कार प्रणाली में गुणवत्ता से अधिक मात्रा को महत्व दिया जाता है।दूसरा महत्वपूर्ण कारण शिकारी जर्नल और सम्मेलन हैं, जो शोधकताओं से शुल्क लेकर तेजी से प्रकाशन का वादा करते हैं, लेकिन उचित समीक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं करते। इससे निम्न गुणवत्ता के और कभी-कभी नकल वाले शोध पत्र प्रकाशित हो जाते हैं।

हाल के वर्षों में सम्मेलनों के स्वरूप में भी बदलाव आया है। पहले जहां सख्त शैक्षणिक मानकों वाले सम्मेलन होते थे, अब कई सम्मेलन केवल आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, कई युवा शोधकताओं में शोध लेखन और अनुसंधान पद्धति की उचित समझ का अभाव होता है। मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की कमी के कारण वे उच्च गुणवत्ता का शोध नहीं कर पाते।तकनीक का उपयोग भी दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह सहयोग और जानकारी तक पहुंच आसान बनाती है, वहीं दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट के दुरुपयोग से नकल और अनैतिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं।

गिरते अनुसंधान मानकों का प्रभाव

यदि निम्न स्तर का शोध सामान्य हो जाता है, तो शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। समाज, उद्योग और सरकार का भरोसा शोध की विश्वसनीयता पर आधारित होता है।कमजोर शोध के कारण गलत डेटा और भ्रामक निष्कर्ष सामने आ सकते हैं, जिससे प्रबंधन, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, निम्न गुणवत्ता वाले सम्मेलनों और प्रकाशनों में समय, धन और बौद्धिक संसाधनों की बबार्दी होती है। यदि अच्छे और खराब शोध को समान महत्व दिया जाता है, तो ईमानदार शोधकताओं का मनोबल भी गिर सकता है।

अनुसंधान मानकों को सुधारने के उपाय

विश्वविद्यालयों को सख्त नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि शोधकर्ता केवल प्रतिष्ठित जर्नल और सम्मेलनों में ही अपने शोध प्रकाशित करें।शोध में नैतिकता, प्लेगियारिज्म और ईमानदारी पर प्रशिक्षण आवश्यक है, जिससे शोधकताओं में सही प्रक्रियाओं की समझ विकसित हो।शैक्षणिक मूल्यांकन को शोध की गुणवत्ता और प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल संख्या के आधार पर। जर्नल संपादकों और सम्मेलन आयोजकों को भी कठोर समीक्षा प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय और बहु-संस्थागत सहयोग से भी शोध की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

शैक्षणिक समुदाय के लिए परिणाम

अनुसंधान गुणवत्ता में गिरावट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।शैक्षणिक संस्थानों को उच्च नैतिक और पद्धतिगत मानकों को बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।शोधकताओं को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने शोध को प्रकाशित करने से पहले जर्नल और सम्मेलनों की विश्वसनीयता की जांच करें।यदि शैक्षणिक समुदाय ईमानदारी, पारदर्शिता और कठोरता को अपनाता है, तो शोध में विश्वास बहाल किया जा सकता है और शैक्षणिक सम्मेलन पुनः ज्ञान-विनिमय के प्रभावी मंच बन सकते हैं।

गँवार किसान

एक किसान था। वह पढ़ा-लिखा नहीं था। वह अकसर लोगों को अखबार व किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। वह सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता, तो तैं भी इन लोगो की तरह पढ़ सकता। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लाना चाहिए।

एक दिन वह शहर गया। चश्मे की एक दुकान में पहुँचकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह-तरह के चश्मे दिखाए। उसने पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। किसान ने एक-एक कर अनेक चश्मे लगाकर देखे। पर वह कुछ भी नही पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है।

दुकानदार ने शंकाभरी नजर से किसान की ओर देखा। फिर उसकी नजर किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी।

दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हे पढ़ना नहीं आता?

किसान ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। इसीलिए तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ, ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूँ। पर इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नही पा रहा हूँ

दुकनदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी का पता चला, तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी रोक सका।

उसने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम बहुत भोले और अज्ञानी हो। सिर्फ चश्मा लगा लेने भर से किसी को पढ़ना-लिखना नहीं आ जाता! चश्मा लगाने से सिर्फ साफ-साफ दिखाई देने लगता है। पहले तुम पढ़ना-लिखना तो सीखो। फिर तुम्हें बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा।

शिक्षाः अज्ञान ही अंधत्व है।

पंजाब पुलिस, आई.आई.टी. रोपड़ के साथ मिलकर एआई आधारित अपराध नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करेगी

अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में विस्तृत जानकारी अब सिर्फ ह्यएक क्लिकह्न दूर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भगवंत मान सरकार ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के साथ साझेदारी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य अपराधियों का एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करना और ह्यगैंगस्टरां ते वारह्न तथा ह्ययुद्ध नशेयां विरुद्धह्न जैसी मुहिमों को मजबूत करना है, ताकि पंजाब और राज्य से बाहर सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को नष्ट किया जा सके।

इस सहयोग के तहत, आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर राज्य सरकार एआई टूल्स का उपयोग करेगी, जिससे पंजाब पुलिस अपराधियों के नेटवर्क को प्रभावी ढंग से मैप और टारगेट कर सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईआईटी रोपड़ के बीच समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जहां एम्स मोहाली में स्थापित डेटा इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी।

इस साझेदारी के अंतर्गत, आईआईटी रोपड़ उन्नत सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, वॉयस रिकग्निशन तकनीक और डैशबोर्ड-आधारित मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे रीयल-टाइम ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग संभव होगी, जिससे विदेशों से चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।

यह पहल पंजाब पुलिस को एक विस्तृत और एकीकृत अपराधी डेटाबेस तैयार करने में सक्षम बनाएगी, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों प्रकार के डेटा को जोड़ा जाएगा। इसमें स्कैन की गई पीडीएफ फाइलों और हस्तलिखित रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे बिखरी हुई जानकारी को तुरंत एक्सेस किया जा सकेगा। भगवंत मान सरकार और आईआईटी रोपड़ मिलकर ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, जिससे बिखरे हुए डेटा को एआई टूल्स, प्रेडिक्टिव मॉडल्स और एनालिटिकल डैशबोर्ड के माध्यम से उपयोगी जानकारी में बदला जा सकेगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होगी।

राज्य सरकार ने आधुनिक पुलिसिंग में डेटा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां स्ट्रक्चर्ड डेटा का विश्लेषण आसान होता है, वहीं पुलिस रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड रूप में होता है, जैसे हस्तलिखित रिपोर्ट और स्कैन किए गए दस्तावेज। इनका एकीकरण न होने से जांच प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यह प्रोजेक्ट अनस्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड को बदलकर उन्हें मौजूदा डेटासेट्स के साथ जोड़कर एक एकीकृत प्रणाली में शामिल करता है, जिससे जांच की कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।

एक वरिष्ठ पंजाब पुलिस अधिकारी ने कहा, आईआईटी रोपड़ के साथ यह साझेदारी पुलिस फोर्स की एआई और मशीन लर्निंग क्षमताओं को मजबूत करेगी। पुलिस कर्मी अपराध के पैटर्न की पहचान करने के लिए बेहतर तरीके से लैस होंगे, जो ह्यगैंगस्टरां ते वारह्न मुहिम को और प्रभावी बनाएगा और अपराधियों द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकेगा।

अधिकारी ने आगे कहा, हमारा मकसद अपराधियों से एक कदम आगे रहना और उनके नेटवर्क को निशाना बनाना है। गैंगस्टर विदेशों से ऑपरेट करते हैं और यहां के युवाओं को अपराध के लिए उकसाते हैं। यह सहयोग एआई के जरिए अपराधियों की ह्यपहचान और रोकथामह्न को और मजबूत करेगा। यह पंजाब पुलिस को एक सुविधाजनक डेटाबेस बनाने में मदद करेगा, जिसमें अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी को व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जा सकेगा और एआई आधारित टूल्स के माध्यम से इसका प्रभावी मूल्यांकन, पूछताछ और विश्लेषण किया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्रोतों के बीच की खाई को भरने का भी उद्देश्य रखता है। इसके तहत ऐसी प्रणाली तैयार की जा रही है जो अनस्ट्रक्चर्ड दस्तावेजों को अपने में शामिल करके उन्हें मौजूदा स्ट्रक्चर्ड डेटासेट्स के साथ जोड़कर एक समेकित और सुविधाजनक डेटाबेस तैयार करेगी।

यह प्रोजेक्ट अपराध की पहचान में तेजी लाने, अपराधी नेटवर्क की निगरानी को मजबूत करने और डेटा-आधारित तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे पंजाब में जन सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए 352 करोड़ से अधिक राशि जारी बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा हुई मजबूत : डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मार्च माह के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 352 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

आगे जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा हर महीने 23,51,338 बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनेक बुजुर्गों के लिए यह पेंशन जीवन की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया

- पंजाब भर में 23.51 लाख से अधिक बुजुर्गों को मासिक पेंशन का लाभ
- 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिली और

कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जिन आवेदकों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित (नहरी/चाही) भूमि, या 5 एकड़ तक बारानी भूमि, या पानी वाले क्षेत्र में 5 एकड़ तक भूमि (पति-पत्नी की संयुक्त भूमि सहित) है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए और लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर जांच की जाए ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग लाभ से वंचित न रहे और पारदर्शी तरीके से राशि लाभार्थियों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों को समाज की अनमोल धरोहर मानती है और उनकी भलाई तथा सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा मृतक पी.आर.टी.सी. कंडक्टर के परिवार को 40 लाख रुपये का बीमा चेक भेंट

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

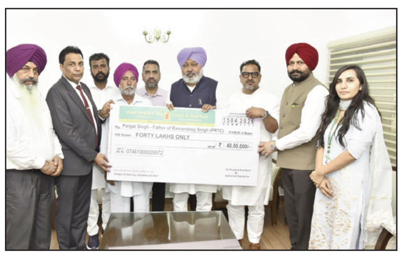

पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) के दिवंगत कंडक्टर रमनदीप सिंह के परिवार के साथ गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें 40 लाख रुपये का बीमा चेक भेंट किया। रमनदीप सिंह ने ड्यूटी के दौरान दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी। जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव घुमियारा के निवासी रमनदीप सिंह 2 जनवरी 2017 को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पी.आर.टी.सी. में कंडक्टर के रूप में भर्ती हुए थे। इस अवसर पर मंत्री द्वारा मृतक के पिता प्रगट सिंह को यह चेक सौंपा गया। इस दौरान, परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह मुआवजा पी.आर.टी.सी. और पंजाब एंड सिंध बैंक के बीच हुए बीमा समझौते के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट बीमा शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य शोकग्रस्त परिवार को आर्थिक सहायता देना है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भगवंत मान सरकार अप्रत्याशित कार्यस्थल हादसों के मद्देनजर अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पी.आर.टी.सी. के चेयरमैन हरपाल जुनेजा, मैनेजिंग डायरेक्टर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल तथा पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और उन्होंने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की।

संक्षिप्त-समाचार

'डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने पूरे पंजाब में जैतो की तमन्ना को 8वीं क्लास में टॉपर आने पर किया सम्मानित

जैतो। फरीदकोट जिले में 8वीं क्लास की सालाना परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉपर स्टूडेंट्स को डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आईएएस ने सम्मानित किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने टॉपर स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को 11000 रुपए के चैक बांटे और उनकी हिम्मत बढ़ाई। गौरतलब है कि जिले के आठवीं क्लास के स्टूडेंट्स में तमन्ना सरस्वती सीनियर सैकेंडरी स्कूल जैतो ने 600/600 मार्क्स लेकर पंजाब में पहला स्थान हासिल किया, जबकि जशनदीप कौर संत मोहन दास मेमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोटसुखिया ने 598/600 मार्क्स लेकर पंजाब में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा मनप्रीत कौर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (कन्या) पंजगराई कलां और मुस्कानप्रीत कौर गवर्नमेंट हाई स्कूल, धीमानवाली ने 585/600 मार्क्स लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत और लगन ही उनकी सफलता का असली मंत्र है और जिले के ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स दूसरों के लिए प्रेरणा का सोर्स हैं। उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स की भूमिका की भी तारीफ की और कहा कि उनके सपोर्ट से ही स्टूडेंट्स ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम अंजना कौंसिल, मिस्टर जसबीर सिंह जस्सी, प्रिंसीपल दीपक कुमार, हेड मास्टर रविंदर सिंह, सोनी थापर, कुसम कालरा के अलावा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौजूद थे।डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर जैतो की पंजाब भर में टापर रही तमन्ना को सम्मानित करते हुए।

17 वां वार्षिक श्री श्याम महोत्सव 18 को

जैतो। क्षेत्र की प्रसिद्ध धार्मिक संस्था श्री श्याम प्रचार मंडल इकाई जैतो की तरह से श्री श्याम का 17वां वार्षिक महोत्सव 18 अप्रैल को रामलीला मैदान जैतो में बड़ी धूमधाम व आस्था से मनाया जा रहा है। यह जानकारी श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष अजय बांसल, चेयरमैन चंद्र मोहन बांसल, सचिव संधीर गर्ग बरगाडी वाले व कोषाध्यक्ष सुरेश गोयल चांदी ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि इस महोत्सव के मुख्य अतिथि जैतो के विधायक व संत रिषी राम जी जलाल वाले होंगे जबकि मुख्य यजमान ए.बी.कोटसपिन इंडिया लि.के एम.डी.दीपक गर्ग,पूजन कर्ता मोहन लाल सिंगला, ध्वज पूजन अशोक कुमार मित्तल व कृष्ण मित्तल, दरबार पूजन मोहित बांसल, दरबार श्रंगार अंकुर गर्ग पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक दीपक लक्खा,आकाश सागर व कुमार नितिन अपनी मधुर आवाज से भजनों द्वारा श्रद्धालुओं को आत्म विभोर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वार्षिक समारोह के मुख्य आकर्षण भव्य दरबार, आलौकिक श्रृंगार, छप्पन भोग होगा। इस अवसर पर विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर गोनी मित्तल,शैरी गर्ग,गोला अग्रवाल,नवल सीए, प्रेम नाथ प्रेमी, वरूण लोहिया व अमन बांसल आदि मौजूद रहे। श्री श्याम प्रचार मंडल जैतो प्रबंधक कमेटी ने कहा कि इस वार्षिक महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री श्याम महोत्सव को लेकर आम जनता विशेष कर महिलाओं में भारी उत्साह पाया जा रहा है।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 6,000 रुपये रिश्वत लेते प्रिंसिपल को रंगे हाथों काबू किया गया

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के दौरान कैंप खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजीतसर मोही, जिला लुधियाना (सरकारी सहायता प्राप्त) में तैनात प्रिंसिपल गुरमीत सिंह को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव मोहित, जिला लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने कोविड काल के दौरान 10वीं कक्षा पास की थी, लेकिन उसे अभी तक 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ था। उसने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया था, परंतु वह भी उसे नहीं मिला। इसके बाद वह अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया। इस दौरान आरोपी प्रिंसिपल ने उससे 15,800 रुपये रिश्वत की मांग की और मौके पर ही उससे 10,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले भी लिए। उल्लेखनीय है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सरकारी फीस 900 रुपये तथा तत्काल फीस 2,000 रुपये है। रिश्वत देने के लिए तैयार न होने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना से संपर्क किया।

विजिलेंस ब्यूरो ने कानूनगो को 33,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला एस.बी.एस. नगर की तहसील बलाचौर, सर्कल काठगढ़ में तैनात कानूनगो रमन कुमार को 33,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी एस.बी.एस. नगर के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि माननीय अदालत ने शिकायतकर्ता की जमीन की निशानदेही के आदेश दिए थे और यह कार्य आरोपी रमन कुमार को सौंपा गया था। शिकायतकर्ता के काम को जटिल बताते हुए आरोपी ने उससे 80,000 रुपये रिश्वत की मांग की। इसमें से उसने शिकायतकर्ता से 33,000 रुपये (15,000 रुपये नकद और 18,000 रुपये ऑनलाइन/क्यूआर कोड के माध्यम से) रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। रिश्वत लेने के संबंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन लेन-देन के विवरण सहित अन्य संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों काबू किया गया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम के दौरान माल दफ्तर पायल, जिला लुधियाना में तैनात पटवारी हरकिंदर सिंह को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तहसील पायल, जिला लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी पटवारी ने शिकायतकर्ता से उसकी जमीन के इंतकाल में संशोधन करने के बदले 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में आरोपी पहले ही 5,000 रुपये पहली किस्त के रूप में ले चुका था।

शिकायतकर्ता द्वारा गैर-कानूनी रिश्वत देने से इनकार करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना से संपर्क किया गया। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों काबू कर लिया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

सीसीए पंजाब सर्कल कार्यालय ने जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया

सिटी दर्पण संवाददाता
लुधियाना

संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए), पंजाब सर्कल के कार्यालय ने पेंशनभोगियों की सुविधा और उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 15 अप्रैल, 2026 को बीएसएनएल जीएमटीडी कार्यालय, भारत नगर चौक, लुधियाना में सफलतापूर्वक एक जीवन प्रमाण पत्र (छउ) शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 60 पेंशनभोगियों ने भाग लिया।

इस शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करना और पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली पेंशन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। शिविर के दौरान, अधिकारियों ने पेंशनभोगियों को मौके पर सहायता प्रदान की और पेंशन संबंधी मामलों, आवश्यक दस्तावेजों और पेंशन प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन दिया।

शिविर में जीवन प्रमाण, ऑनलाइन पेंशन सेवाओं और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य नागरिक-केंद्रित पहलों जैसी डिजिटल सेवाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा की गई, जिससे पेंशनभोगी अपने घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, प्रतिभागियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की गई।

साथ ही, पेंशनभोगियों को साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें फर्जी कॉल/मैसेज, फिशिंग के प्रयासों से बचने और व्यक्तिगत व बैंकिंग जानकारी को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

पेंशनभोगी संघों ने संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) पंजाब, श्री विजेंद्र एन. टंडन के कार्य और नेतृत्व की सराहना की, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिला है। भाग लेने वाले पेंशनभोगियों ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है और सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और सुविधाजनक बनती हैं।

सीसीए पंजाब की टीम भविष्य में भी विभिन्न जिलों में इसी तरह के आउटरीच शिविर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पेंशनभोगियों के लिए समय पर, कुशल और सुरक्षित सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

उक्त मॉड्यूल के चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी नेटवर्क से भी जुड़े तार सामने आए: डीजीपी गौरव यादव

आई.एस.आई. समर्थित सीमा पार के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; चार हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल सहित एक व्यक्ति अमृतसर से गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर आई.एस.आई. समर्थित सीमा पार के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आरोपी के कब्जे से चार पी-86 हैंड ग्रेनेड और गोलियों सहित दो विदेशी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सागर सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर के गल्लूवाल गांव का रहने वाला है। यह

- गिरफ्तार आरोपी एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने विदेशी हैंडलर के संपर्क में था: डीजीपी गौरव यादव

कार्रवाई स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और एसएसओसी मोहाली द्वारा संयुक्त रूप से की गई। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी विदेशी हैंडलरों के निदेर्शों पर काम कर रहा था और चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी मॉड्यूल से उसके संबंध सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान, ट्रैकिंग और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से हैंड ग्रेनेड और हथियारों की एक खेप भेजी गई है, जिसे भारत में सक्रिय मॉड्यूल के स्थानीय सहयोगियों ने प्राप्त कर लिया है और वे आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान आरोपी सागर सिंह को अमृतसर के खासा-राम तीर्थ रोड से गिरफ्तार किया गया।

एआईजी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जनवरी 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी हैंडलरों के संपर्क में आया था और तभी से उनके निदेर्शों पर काम कर रहा था। उसने उनके कहने पर हथियारों और गोला-बारूद की खेप प्राप्त कर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाई, जिसके बदले उसे पैसे दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि पैसों के लालच में आरोपी इस कार्य के लिए तैयार हुआ।

उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2026 में आरोपी सागर सिंह को अमृतसर देहाती पुलिस ने हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया था और मार्च 2026 में जमानत मिलने के बाद उसने एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने हैंडलर से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया और फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। इस सम्बन्धी ओर जाँच जारी है।

इस संबंध में पुलिस थाना एसएसओसी अमृतसर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) (डी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 22, दिनांक 15.04.2026 दर्ज की गई है।

तुर्किये में स्कूल में गोलीबारी, पांच और ने दम तोड़ा, अब तक नौ की मौत

13 वर्षीय छात्र ने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से सहपाठियों पर चलाई गोलियां

24 घंटे में स्कूल पर दूसरा बड़ा हमला

एजेंसी (हि.स.)

अंकारा

तुर्किये के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक मिडिल स्कूल में बुधवार को हुई गोलीबारी में घायल 20 लोगों में पांच और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। घायलों में छह की हालत गंभीर है। यह जानकारी बुधवार को गृहमंत्री मुस्तफा सिफ्टसी ने दी। ओनिकिसुबात जिले के आयसेल कैलिक मिडिल स्कूल में करीब 13 साल के एक छात्र ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस घटना से ठीक एक दिन पहले एक अन्य स्कूल में एक हमलावर ने 16 लोगों को घायल कर दिया था और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कहमनमारास के गवर्नर मुकर्रम उनलुअर ने बताया कि इस ताजा हमले में एक शिक्षक और तीन छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के दौरान हमलावर की भी मौत हो गई।

फोटोः हि.स.

मुस्तफा सिफ्टसी ने कहमनमारास शहर से जारी बयान में कहा, हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि नौ लोगों की मौत हो गई है। घायलों में से छह लोग फिलहाल इंटेंसिव केयर में हैं। इनमें से तीन की हालत अत्यधिक गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि उनलुअर ने पत्रकारों को बताया, एक छात्र अपने बैग में बंदूकें लेकर स्कूल आया था। हमारा मानना है कि ये बंदूकें उसके पिता की थीं। वह दो क्लासरूम में घुसा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि हमलावर ने पांच बंदूकों और सात मैगजीन का इस्तेमाल किया। उनलुअर ने बताया कि हमलावर आठवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सानलिउर्फा प्रांत के सिवेरेक जिले में एक पूर्व छात्र ने अपने पुराने हाईस्कूल में एक शॉटगन से गोलीबारी की। इस घटना में 16 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर उसने आत्महत्या कर ली।

राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संसद में वादा किया कि स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में जिन लोगों की लापरवाही या गलती पाई जाएगी उनसे निश्चित रूप से जवाब मांगा जाएगा। एर्दोगन ने बताया कि मंगलवार के हमले के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और चार अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से निलंबित कर दिया है। स्कूल को चार दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अब से पहले तुर्किये में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती थीं। मई 2024 में इस्तांबुल में एक छात्र ने स्कूल से निकाले जाने के पांच महीने बाद एक निजी हाई स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

नेपाल में 10 वर्ष से निष्क्रिय बैंक खाते होंगे सील साढ़े 17 अरब रुपया जमा होगा सरकारी खजाने में

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल सरकार ने 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को सील करते हुए उसमें रहे में लगभग साढ़े 17 अरब रुपये सरकारी खाता में लाने का निर्देश दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्वनाथ पौडेल के अनुसार, इस वर्ष मार्च महीने के अंत तक निष्क्रिय खातों में कुल 1763 करोड़ रुपये जमा है। ऐसे खातों की संख्या 36 लाख 45 हजार 593 बताई गई है। पौडेल ने कहा कि सरकार ने इन सभी खातों को सील करते हुए इनमें जमा सभी रकम को सरकारी खाते में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बैंक तथा वित्तीय संस्थान संबंधी ऐन के अनुसार, लंबे समय से निष्क्रिय खातों का विवरण हर वर्ष राष्ट्र बैंक को भेजना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत आर्थिक वर्ष 2025/26 तक बैंकों द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार यह आंकड़ा सामने आया है। नई सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिपरिषद् बैठक में स्वीकृत शासकीय सुधार के 100 कार्यसूची के 78वें बिंदु में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय बैंक खातों की राशि को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सरकारी कोष में लाने की बात कही गई है।

गवर्नर पौडेल ने कहा इसी के तहत यह राशि बैंक खातों से सरकारी कोष में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, निष्क्रिय खातों में औसत जमा राशि लगभग 5 हजार रुपये है, जो आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब 10 वर्ष से पुराने खातों की राशि को सरकारी कोष में लाने के निर्णय के बाद लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं यह राशि जब्त तो नहीं हो जाएगी।

नेपाल में 100 से अधिक नए कानून लाने की तैयारी

काठमांडू। नेपाल सरकार 100 से अधिक नए कानून बनाने और मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विषयों की पहचान का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार के प्रवक्ता तथा शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के मुताबिक कुल 103 नए कानूनों के विषय और संशोधन किए जाने वाले कानूनों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर नए कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के कार्यालय सहित सभी 22 मंत्रालय काम कर रहे हैं। पोखरेल ने जानकारी दी है कि कानून निर्माण की रूपरेखा और विधायी प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी हुई हैं या नहीं, इसका निरीक्षण कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर अन्य मंत्रालयों को कानून निर्माण के लिए निर्देश देने का काम भी यही मंत्रालय कर रहा है। 100 से अधिक नए कानूनों के निर्माण और संशोधन के लिए तैयार विषय सूची में से 40 से 45 विधेयकों को आगामी संघीय संसद के सत्र में पारित कराने की सरकार की तैयारी है।

पाकिस्तान के खैबर- पख्तूनख्वा प्रांत में मुठभेड़ जारी, दो आतंकी ढेर

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के खैबर- पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस और सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने बुधवार आधीरात बाद बगटू टॉप सरकी और चंबा गुल इलाकों को घेर लिया। पुलिस का कहना है कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस बड़े अभियान में दो आतंकवादी मारे गए और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया।दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कोहाट के उच्च पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई घंटों से यह अभियान चल रहा है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक घिर चुके सभी आतंकवादी मार नहीं दिए जाते। कोहाट के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह अभियान अब निर्णायक दौर में है।

संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के लिए 100 करोड़ रुपये की मानवीय सहायता मंजूर की

न्यूयॉर्क/तेहरान। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध प्रभावित ईरान के लिए 12 मिलियन डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) की आपात मानवीय सहायता जारी करने की घोषणा की है। यह सहायता देश में बिगड़ते हालात और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि करीब 40 दिनों तक चले संघर्ष के कारण हजारों नागरिकों की मौत हुई है, जबकि बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसी जरूरी सेवाएं भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह फंड विभिन्न साझेदार संगठनों के जरिए जमीनी स्तर पर राहत कार्यों को तेज करने में मदद करेगा। इसके तहत प्रभावित लोगों तक भोजन, चिकित्सा सहायता, स्वच्छ पानी और अन्य जरूरी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मौजूदा हालात में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। ऐसे में यह आर्थिक मदद जीवन रक्षक साबित हो सकती है। मानवीय एजेंसियों का कहना है कि संघर्ष के चलते हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं और अगर जल्द ही स्थायी समाधान नहीं निकला, तो संकट और गहरा सकता है।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार को लगे मुनाफा वसूली के झटके

बिकवाली के बावजूद हरे निशान में सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

मजबूत ग्लोबल संकेतों के सपोर्ट से घरेलू शेयर बाजार में वीरवार शुरूआती कारोबार के दौरान मजबूती बनी हुई है। आज के कारोबार की शुरूआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के कुछ देर बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। इसके बावजूद ये दोनों सूचकांक फिलहाल हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.19 प्रतिशत और निफ्टी 0.21 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। वीरवार प्रातः 10

फोटोः हि.स.

बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इंफोसिस और लार्सन एंड टूब्रो के शेयर 2.73 प्रतिशत से लेकर 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, सन फार्मास्युटिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया और नेस्ले के शेयर 0.86 प्रतिशत से लेकर 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,746 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,866 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 880 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 20 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 10 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 32 शेयर हरे निशान में और 18 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज 566.32 अंक की मजबूती के साथ 78,677.56 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरूआत होने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से यह सूचकांक उछल कर 78,730.32 अंक के स्तर तक पहुंचा। इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से सेंसेक्स की चाल में गिरावट आ गई।

संक्षिप्त-समाचार

स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रतियां जलाईं

नामक्कल। द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज परिसीमन विधेयक, 2026 की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संसद का विशेष सत्र आज शुरू हो रहा है। इस सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया जाना है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। खास तौर पर, इस विधेयक के खिलाफ द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुरू से ही अपना कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक के विरोध में तमिलनाडु भर में घरों पर काला झंडा फहराने का आह्वान किया है। नामक्कल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने काली शर्ट पहनकर ध्वजस्तंभ पर काला झंडा फहराया और परिसीमन विधेयक की प्रतियों को जलाकर, 'लड़ेंगे, लड़ेंगे' तमिलनाडु लड़ेगा' जीतेंगे हम साथ मिलकर' के नारे लगाए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु भर में विरोध की आग फैलने दो।

राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने साइकिल से पहुंचे तेरेस गोवाला

गुवाहाटी/नई दिल्ली। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद तेरेस गोवाला ने सादगी और अपने अतीत की यादों को ताजा करते हुए संसद भवन पहुंचने के लिए साइकिल का सहारा लिया। उनके इस अनोखे अंदाज ने आज सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तेरेस गोवाला ने दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। आमतौर पर जहां नेता वाहन काफिले के साथ संसद पहुंचते हैं, वहीं उनका यह कदम अलग और खास नजर आया। उनकी इस पहल को सादगी और जड़ों से जुड़े रहने का संदेश माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में पहुंचकर शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कीं।

मंडल कारा में डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, नहीं मिला अवैध समान

अररिया। डीएम विनोद दूहन और एसपी जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की सुबह आरएस स्थित मंडल कारा में छापेमारी की गई।छापेमारी में डीएम एसपी के अलावे सदर एसडीएम,सदर एसडीपीओ,डीएसपी यातायात,साइबर डीएसपी,नगर थानाध्यक्ष समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे।छापेमारी में कई थाना की पुलिस को भी लगाया गया था। अधिकारियों ने कैदियों के बैरक,कैदियों के समान एवं अन्य संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई।प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर छापेमारी किया गया,जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और मौके पर डीएम और एसपी ने जेल की सुरक्षा में लगे जेल अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों और बलों को सुरक्षा के मद्देनजर कई आवश्यक निर्देश दिए।

बहरागोड़ा में फिर मिला संदिग्ध सिलेंडरनुमा बम

पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बरागाड़िया पंचायत के पानीपाड़ा गांव में बुधवार देर रात स्वर्णरेखा नदी के किनारे ग्रामीणों की नजर एक सिलेंडरनुमा वस्तु पर पड़ी, जिसके बाद पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और कुछ ग्रामीणों ने उस वस्तु को नदी से बाहर निकाल लिया। हालांकि बाद में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना पुलिस दल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सतर्कता बरतते हुए बम निरोधक दस्ते को भी सूचित किया है, ताकि तकनीकी जांच के बाद वस्तु की प्रकृति स्पष्ट हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि बरामद वस्तु विस्फोटक है या नहीं। विशेषज्ञों की टीम की ओर से जांच के बाद ही अंतिम रूप से स्थिति साफ हो पाएगी। एहतियातन आसपास के इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि किसी अन्य संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी की संभावना को खारिज किया जा सके।

बीएमसी की स्टैंडिंग कमिटी के बैठक से नगरसेविका का 20 हजार रुपये चोरी

मुंबई। बीएमसी की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक से बुधवार को एक महिला नगरसेवक के पर्स से 20 हजार रुपये चोरी हो गए। इस घटना से मनपा प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्टैंडिंग कमिटी के सभागृह में इस तरह की चोरी की यह पहली घटना बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 56 की शिवसेना (यूबीटी) की नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया के बैग से 20 हजार रुपये चोरी होने की शिकायत की। इस संबंध में उन्होंने महापौर, विपक्ष की नेता और स्थायी समिति के अध्यक्ष से शिकायत की। लक्ष्मी भाटिया के अनुसार उन्होंने समिति कक्ष में अपना पर्स रखा था और उसे वहीं छोड़कर भोजन के लिए चली गईं। वापस आने पर जब उन्होंने पर्स देखा तो उसकी चेन खुली हुई थी और उसमें से 20 हजार रुपये चोरी हो गए थे। इस घटना के बाद बीएमसी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। लक्ष्मी भाटिया ने कहा कि स्थायी समिति को बीएमसी की तिजोरी माना जाता है। यदि वहीं ऐसी घटना हो रही है, तो सुरक्षा पर क्या भरोसा किया जाए? उन्होंने बताया कि बैठक खत्म होने के बाद सभी लोग भोजन के लिए गए थे और उस समय उनका पर्स वहीं रखा था। अंदर कुछ स्टाफ मौजूद था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जांचने की मांग की, लेकिन वहां कैमरे ही नहीं लगे हैं। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है।

सुरक्षा बलों पर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार

चुराचांदपुर (मणिपुर)। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के रेंगकाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक वाहन को रोककर उसमें सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान एस मोल्डुंग निवासी नगामखोमांग हाओकिप (36) और ल्हांगनोम गांव निवासी लेटमिनथांग हाओकिप (38) के रूप में हुई है। विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वाहन को रोककर दोनों को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से एक वाहन और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित सिएलमत पुल पर सुरक्षा बलों पर की गई फायरिंग की घटना में शामिल थे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान को गोली लगने से चोट आई थी। मामले में आगे की जांच जारी है।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत एशिया में भी चौतरफा तेजी का रुख

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में शांति समझौता होने की बढ़ती उम्मीद के बीच ग्लोबल मार्केट से आज पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में आज खरीदारी का रुख बना हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है, कह कर पिछले सत्र के दौरान वॉल स्ट्रीट में जोश का माहौल बना दिया। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.80 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,022.95 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 376.93 अंक यानी 1.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,016.02 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 48,514.27 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

फोटोः हि.स.

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,559.58 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,274.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,066.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल बना हुआ है। एशिया के सभी प्रमुख नौ बाजार के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 143 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,392.50 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 251.39 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,973.53 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

निक्केई इंडेक्स ने आज जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,320.76 अंक यानी 2.27 प्रतिशत उछल कर 59,455 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 115.82 अंक यानी 1.90 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,207.21 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। हैंग सेंग इंडेक्स में भी आज जबरदस्त तेजी नजर आ रही है।

नेपाल में डीजल और मिट्टी का तेल हुआ 30 रुपये प्रति लीटर महंगा

काठमांडू। नेपाल आयल निगम ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आज एक बार फिर वृद्धि की है। नई मूल्य सूची के अनुसार, डीजल और मिट्टी के तेल (केरोसीन) की कीमत में प्रति लीटर 30 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि हवाई ईंधन में प्रति लीटर 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। संशोधित दरों के अनुसार डीजल और मिट्टी के तेल का मूल्य प्रति लीटर 237 रुपये और हवाई ईंधन का मूल्य प्रति लीटर 256 रुपये हो गया है। निगम का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भेजी गई नई मूल्य सूची के आधार पर गणना करने पर अभी भी भारी घाटा बना हुआ है। लागत मूल्य अधिक और बिक्री मूल्य कम होने के कारण मूल्य समायोजन के बाद भी पेट्रोल पर प्रति लीटर 2 रुपये 32 पैसे, डीजल पर 87 रुपये 99 पैसे, मिट्टी के तेल पर 36 रुपये 70 पैसे और खाना पकाने वाले एलपी गैस पर प्रति सिलेंडर 331 रुपये 25 पैसे का घाटा कायम है। निगम की विज्ञप्ति के अनुसार, पखवाड़े के आधार पर कुल लगभग 7 अरब 81 करोड़ 61 लाख रुपये का घाटा हो रहा है।

ओली और लेखक के खिलाफ हत्या मामले में जांच तेज, पुलिस को मिला 'वर्किंग ऑर्डर'

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

जिला अदालत काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के खिलाफ हत्या से जुड़े मामले की जांच के लिए पुलिस को चार बिंदुओं वाला कायार्देश दिया है। जिला सरकारी वकील कार्यालय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ओली और लेखक पिछले एक हफ्ते से हाजिरी जमानत पर बाहर हैं। हालांकि उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। दोनों को जरूरत पड़ने पर पुलिस के सामने उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर रिहा किया गया है। इनकी रिहाई के बावजूद मामले की जांच न रोकने के लिए सरकारी वकील कार्यालय ने पुलिस को चार निर्देश दिए हैं।

पहले निर्देश में कहा गया है कि 8 सितंबर 2025 को जेन जी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं में मारे गए सभी व्यक्तियों के पोस्टमार्टम संबंधित

फोटोः हि.स.

दस्तावेज संलग्न किए जाएं। इसके अलावा, 8 सितंबर 2025 की घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान कर उनके बयान दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। तीसरे बिंदु में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में शामिल करने को कहा गया है। इस दौरान अगर नए तथ्य आते हैं तो आरोपितों के अतिरिक्त बयान लेने का निर्देश दिया गया है। ओली और लेखक की रिहाई पूरक बयान के लिए उपस्थित होने की शर्त पर की गई है।

जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एसपी पवन कुमार भट्टराई के अनुसार, अदालत और सरकारी वकील कार्यालय के निर्देशों के अनुसार दोनों की रिहाई के बावजूद मामले की जांच जारी है। ओली और लेखक का प्रारंभिक बयान दर्ज किया जा चुका है।

डिवाइडर पार कर पलटी स्लीपर बस तीन की मौत, 20 से ज्यादा घायल

एजेंसी (हि.स.)

कोटा

शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में नयागांव पुलिया के पास बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा रात में उस समय हुआ जब एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में घुस गई और पलट गई। पुलिस के अनुसार निजी कंपनी की यह बस अहमदाबाद से ग्वालियर-भिंड जा रही थी, जिसमें अधिकांश यात्री मध्यप्रदेश के थे। बस के पलटते ही उसमें सवार यात्री अंदर फंस गए और कई लोग टूटे कांच से बाहर सड़क पर गिर गए। हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई, वे ड्राइवर केबिन में बैठे थे। बस पलटने के दौरान केबिन का फ्रंट मिरर टूट गया और ये लोग सड़क पर गिर गए। उसी समय सामने से आ रहे ट्रॉले ने उन्हें कुचल दिया। मृतकों में से दो की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके

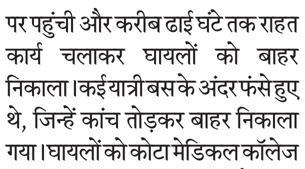

फोटोः हि.स.

पर पहुंची और करीब ढाई घंटे तक राहत कार्य चलाकर घायलों को बाहर निकाला। कई यात्री बस के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। घायलों को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे को लेकर अलग-अलग कारण सामने आ रहे हैं। यात्रियों का दावा है कि बस के फ्रंट मिरर पर किसी ने पत्थर मारा था, जिससे चालक घबरा गया और बस का नियंत्रण खो बैठा। वहीं पुलिस के अनुसार सड़क पर अचानक किसी जानवर के आने की आशंका भी जताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और बस चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जिससे पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पहल

विश्व बैंक ने की 'वॉटर फॉरवर्ड' की घोषणा

एक अरब लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का महा-अभियान

2030 तक 40 करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुँचाएगा बैंक

एजेंसी (हि.स.)

वॉशिंगटन

दुनियाभर में गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच विश्व बैंक ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी वैश्विक कार्यक्रम 'वॉटर फॉरवर्ड' की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अगले चार वर्षों के भीतर दुनिया की एक अरब आबादी को सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक का मानना है कि जल तक पहुँच केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन का आधार है। विश्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कार्यक्रम दो स्तरों पर काम करेगा। पहला, बुनियादी ढांचे का निर्माण और दूसरा, मौजूदा जल प्रबंधन प्रणालियों में नीतिगत

फोटोः हि.स.

सुधार। बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी वित्तीय शक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से वर्ष 2030 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर बेहतर जल सेवाएं प्रदान करेगा। शेष 60 करोड़ लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक साझेदारों और निजी क्षेत्रों का सहयोग लिया जाएगा। 'वॉटर फॉरवर्ड' पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सहभागी ढांचा है। विश्व बैंक इस मिशन में अकेला नहीं है; इसमें कई दिग्गज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। प्रमुख सहयोगी संस्थान- एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्थानीय विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक फंड की वित्तीय सहायता। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक की तकनीकी भागीदारी। हालांकि, इस विशाल परियोजना के लिए कुल निवेश की सटीक राशि का खुलासा अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह कई अरब डॉलर का निवेश होगा। वर्तमान में दुनिया के 14 देशों ने आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम के तहत अपनी जल नीतियों में आमूलचूल बदलाव करने और प्रणालियों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है।विश्व बैंक के आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की लगभग आधी आबादी—यानी 4 अरब लोग—वर्ष के किसी न किसी समय जल संकट का सामना करते हैं। इस संकट के पीछे केवल प्रकृति का हाथ नहीं है, बल्कि मानव निर्मित कमियां भी बड़ी बाधा हैं।

संकट के मुख्य कारण

जल वितरण के लिए ठोस सरकारी नियमों का अभाव। जल आपूर्ति प्रणालियों का घाटे में चलना, जिससे रखरखाव और नए निवेश में कमी आती है। अनियमित मानसून, लगातार बढ़ता सूखा और विनाशकारी बाढ़, जो स्थापित प्रणालियों को ध्वस्त कर देती हैं। विश्व बैंक का जोर केवल नए पाइप बिछाने पर नहीं, बल्कि 'गवर्नेंस' यानी शासन व्यवस्था को सुधारने पर है। बैंक का मानना है कि जब तक जल क्षेत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक दीर्घकालिक सुधार संभव नहीं है।

आईपीएल में वापसी के लिए तैयार पैट कमिंस, गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट

फिटनेस टेस्ट पास कर मिला 'ग्रीन सिग्नल', बढ़ी विरोधियों की चिंता

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सिडनी में कराए गए ताजा स्कैन के बाद बिना किसी प्रतिबंध के गेंदबाजी करने की अनुमति मिल गई है, जिससे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को हुए स्कैन में यह पुष्टि हुई कि उनकी पीठ की स्ट्रेस इंजरी, जिसने पिछले साल अगस्त के बाद उन्हें सिर्फ एक पेशेवर मैच खेलने तक सीमित कर दिया था, अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज अब शुक्रवार को भारत लौटेंगे और आईपीएल के बाकी मैचों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ेंगे, जहां वह अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी ट्रैविस हेड के साथ खेलेंगे। हालांकि सनराइजर्स इस सप्ताहांत चेन्नई सुपर किंग्स और अगले बुधवार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मुकाबले खेलेगी, लेकिन कमिंस जल्दबाजी में वापसी नहीं करना चाहते। वह 25 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में प्लेइंग इलेवन में लौटने का लक्ष्य बना रहे हैं। कमिंस के टीम में लौटते ही कप्तानी भी उनके हाथों में वापस आने की संभावना है। उनकी अनुपस्थिति में टीम की कमान ईशान किशन संभाल रहे थे। फिलहाल टीम दो जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। कमिंस की वापसी उनकी योजना के अनुसार है, जिसमें वह टूर्नामेंट के दूसरे चरण और संभावित प्लेऑफ मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एक व्यस्त टेस्ट क्रिकेट कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अगले 12 महीनों में लगभग 21 टेस्ट मैच खेले जा सकते हैं। हाल ही में कमिंस ने तीनों फॉर्मेट में खेलने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट और वनडे कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण सीरीज को प्राथमिकता देंगे और खुद को फिट रखने के लिए दो से तीन महीने का ब्रेक भी लेते रहेंगे। उन्होंने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट' पॉडकास्ट में कहा, मैं अभी भी तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हम इसे संतुलित कर सकते हैं। मुझे टेस्ट क्रिकेट बेहद पसंद है। उम्मीद है कि अगले 3-5 साल तक मैं इसी तरह खेलता रहूं और टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना न पड़े। ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कार्यक्रम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जो डार्विन और मैके में खेली जाएगी। इसके बाद टीम दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट, घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट, फिर अगले साल जनवरी-फरवरी में भारत दौरे पर पांच टेस्ट खेलेगी। मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 150वीं वर्षगांठ टेस्ट और जून में लॉर्ड्स में संभावित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी शामिल है, इसके बाद एशेज सीरीज के पांच टेस्ट मैच होंगे।

करीब 4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी कमिंस के कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। टीम के कोच डेनियल विटोरी ने उनकी फिटनेस को शानदार बताया है।

विटोरी ने कहा, उनकी फिटनेस बेहतरीन रही है क्योंकि वह लंबे समय से मैदान से बाहर थे और इस दौरान उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काफी काम किया। गेंदबाजी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है।

25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल सकते हैं पहला मैच

फोटोः हि.स.

बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी (हि.स.)
म्यूनिख

जर्मनी के दिग्गज क्लब बायर्न म्यूनिख ने स्पेन के रिकॉर्ड 15 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड को बुधवार रात एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराकर (कुल स्कोर 6-4) यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मुकाबले में आखिरी पलों में लुइस डियाज और माइकल ओलिसे के गोल ने बायर्न को यादगार जीत दिलाई। मुकाबले के 89वें मिनट में लुइस डियाज ने गोल कर बायर्न को बढ़त दिलाई, जबकि इंजरी टाइम में माइकल ओलिसे ने गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ बायर्न अब पेरिस सेंट-जर्मेन से भिड़ेगा।

मैच के 86वें मिनट में रियल मैड्रिड के मिडफील्डर एडुआर्डो कामाविंगा को दो पीले कार्ड मिलने के बाद मैदान से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मैच के अंत में आर्डा गुलर को भी असंतोष जताने पर रेड कार्ड मिला, जिससे टीम की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा। मुकाबले की शुरूआत बेहद तेज रही और सिर्फ 35 सेकंड में ही आर्डा गुलर ने गोल कर रियल को बढ़त दिलाई।

फोटोः हि.स.

इसमें बायर्न के गोलकीपर मैनुअल नॉयर की बड़ी गलती रही। हालांकि बायर्न ने पांच मिनट बाद ही अलेक्जेंडर पावलोविच के हेडर से बराबरी कर ली। 29वें मिनट में गुलर ने शानदार फ्री-किक से रियल को फिर बढ़त दिलाई, लेकिन हैरी केन ने आठ मिनट बाद गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद किलियन एम्बाप्पे ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन दोनों टीमों ने मौके बनाए। मैनुअल नॉयर ने शानदार बचाव कर बायर्न को मैच में बनाए रखा। हालांकि अंत में कामाविंगा के रेड कार्ड के बाद बायर्न ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार दो गोल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। बायर्न के कोच विन्सेंट कोम्पनी ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, यह क्लब के लिए शानदार रात रही। टीम ने एकजुटता और आत्मविश्वास दिखाया, जो जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। वहीं रियल मैड्रिड के कोच अल्वारो अर्बेलोआ ने रेड कार्ड पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने बड़े मैच में इस तरह का फैसला खेल की खूबसूरती को प्रभावित करता है। इस जीत के साथ बायर्न म्यूनिख ने शानदार वापसी का उदाहरण पेश किया और अब उसकी नजरें खिताब जीतने पर टिकी हैं।

सीएसके के लिए बड़ा झटका, खलील चोट के कारण आईपीएल से बाहर

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तेज गेंदबाज खलील अहमद कूल्हे में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर हो गए हैं जो अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी इस फ्रेंचाइजी टीम के लिए करारा झटका है।

खलील ने सीएसके की तरफ से अभी तक सभी पांच मैच में हिस्सा लिया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 14 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। उन्होंने अब तक सीएसके की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य सदस्य थे।

आईपीएल के एक सूत्र ने बताया, यह ग्रेड दो की चोट है और इसे ठीक होने में कम से कम 10-12 सप्ताह का समय लगेगा। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 11 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं। भारत की तरफ से उन्होंने अपना आखिरी मैच जुलाई 2024 में खेला था।

पीजीडीएवी कॉलेज ने दर्ज की 175 रन की बड़ी जीत

यश डबास ने लगाया विस्फोटक शतक

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

तीसरे स्वामी दयानंद सरस्वती टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान पीजीडीएवी कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को शिवाजी कॉलेज को 175 रनों के विशाल अंतर से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले के हीरो रहे यश डबास, जिन्होंने महज 51 गेंदों में 161 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के जड़े। उनके अलावा श्रेष्ठ यादव (58) और अंकित कुमार (53) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम के स्कोर को मजबूती दी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पीजीडीएवी कॉलेज ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 332 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में शिवाजी कॉलेज की टीम 15.3 ओवर में 157 रन पर सिमट गई। शिवाजी कॉलेज की ओर से प्रियांश सिंह ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि धैर्य मल्होत्रा ने गेंदबाजी में तीन विकेट हासिल किए। पीजीडीएवी कॉलेज की ओर से वैभव पांडे (13 रन देकर 4 विकेट) और प्रणीत (17 रन देकर 3 विकेट) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। यश डबास को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच' चुना गया, यह पुरस्कार डॉ. पवन डबास ने प्रदान किया। टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में पीजीडीएवी येलो टीम ने शहीद भगत सिंह कॉलेज को 87 रनों से हराया। इस मैच में करण सोनी ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 52 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 11 रन देकर 3 विकेट झटके। नैतिक यादव (40) और अंश जाखड़ (3/38) ने भी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीजीडीएवी येलो टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 265 रन बनाए। जवाब में शहीद भगत सिंह कॉलेज की टीम 19.2 ओवर में 178 रन पर ऑलआउट हो गई। पराजित टीम की ओर से वरदान सूरी ने 23 रन बनाए, जबकि अभय और शास्वत ने दो-दो विकेट हासिल किए।

फोटोः हि.स.

लयोनेल मेस्सी पर 70 लाख डॉलर के अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप

एजेंसी (हि.स.)
मियामी

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी पर मियामी स्थित एक इवेंट प्रमोटर' ने मुकदमा दायर किया है, जिसका कहना है कि इस दिग्गज खिलाड़ी ने पिछले साल एक प्रदर्शनी मैच में अनुपस्थित रहकर 70 लाख डॉलर के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार विड म्यूजिक ग्रुप ने पिछले महीने मियामी-डेड सर्किट कोर्ट में मेस्सी और अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) के खिलाफ धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। मेस्सी और एएफए ने इस संबंध में टिप्पणी के लिए भेजे गए सवालों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मेस्सी को महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वह मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम दोनों के लिए खेलते हैं और प्रशंसक उन्हें खेलते हुए देखने के लिए अक्सर बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं। मुकदमे के अनुसार विड ने पिछले साल गर्मियों में अर्जेंटीना के वेनेजुएला और प्यूर्टोरिको के खिलाफ होने वाले मैत्री मैचों के लिए एएफए के साथ एक समझौता किया था। विड का दावा है कि मेस्सी को प्रत्येक मैच में कम से कम 30 मिनट खेलना था, बशर्ते कि वह घायल न हों। मेस्सी वेनेजुएला के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे।

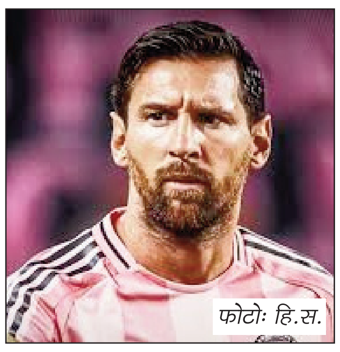
फोटोः हि.स.

दर्पण विशेष

विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026: 'निदानः देखभाल का पहला कदम'

हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्तस्राव विकार है जिसमें कुछ थक्के बनाने वाले कारकों की कमी के कारण रक्त ठीक से नहीं जमता। इसका मतलब है कि एक छोटी सी चोट भी सामान्य से अधिक समय तक रक्तस्राव का कारण बन सकती है, और कुछ मामलों में जोड़ों या मांसपेशियों के अंदर भी रक्तस्राव हो सकता है। शीघ्र पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि समय पर उपचार गंभीर जटिलताओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। प्रत्येक वर्ष, विश्व हीमोफीलिया दिवस रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता, शीघ्र परीक्षण और उपचार तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह ब्लॉग हीमोफीलिया के शुरूआती लक्षणों, इस स्थिति के निदान की प्रक्रिया और शीघ्र पहचान जीवन रक्षक कैसे हो सकती है, इस बारे में बताता है।

इतिहास और महत्व

विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना विश्व हीमोफीलिया संघ ने 1989 में की थी। यह तिथि फ्रैंक श्नाबेल के जन्मदिन के सम्मान में चुनी गई थी, जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की और हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और सहायता में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस वैश्विक दिवस का उद्देश्य रक्तस्राव विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जिनका निदान नहीं हो पाता या जिन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता। इस दिवस पर जागरूकता अभियान शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करते हैं, लक्षणों के बारे में जानकारी बढ़ाते हैं और चिकित्सा देखभाल और सहायता सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस इस बात की भी याद दिलाता है कि शीघ्र निदान और उचित प्रबंधन से हीमोफीलिया से जुड़ी जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विश्व हीमोफिलिया दिवस 2026 का थीम

2026 के विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय है 'निदानः देखभाल का पहला कदम'। विश्व हीमोफीलिया महासंघ द्वारा घोषित यह विषय हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों के लिए शीघ्र और सटीक निदान के महत्व पर प्रकाश डालता है। दुनिया भर में कई व्यक्ति बिना निदान के रह जाते हैं, जिससे उपचार में देरी होती है और जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। 2026 का विषय रक्तस्राव विकारों के बारे में अधिक जागरूकता, निदान परीक्षणों तक बेहतर पहुंच और शीघ्र चिकित्सा मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर देखभाल और उचित उपचार मिल सके।

हीमोफिलिया क्या है?

हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवंशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता। सामान्यतः रक्त का थक्का जमना कई प्रोटीनों की एक श्रृंखला द्वारा होता है जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ये प्रोटीन चोट लगने के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर का स्तर बहुत कम होता है या अनुपस्थित होता है। परिणामस्वरूप, कटने, चोट लगने, दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं या सर्जरी के बाद रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक जारी रह सकता है। यह स्थिति आमतौर पर जन्म से ही मौजूद होती है और क्लॉटिंग फैक्टर उत्पन्न करने वाले जीन में परिवर्तन के कारण होती है। हीमोफीलिया मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है, हालांकि महिलाएं भी इस जीन की वाहक हो सकती हैं और कभी-कभी उनमें हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई लोगों को सबसे पहले इस स्थिति का पता बार-बार नील पड़ने, छोटी-मोटी चोटों से लंबे समय तक रक्तस्राव होने या जोड़ों के अंदर रक्तस्राव के कारण सूजन और दर्द से चलता है।

हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है?

हीमोफीलिया को मुख्य रूप से रक्त में कम या अनुपस्थित थक्का जमाने वाले कारक के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हीमोफीलिया के दो मुख्य प्रकार नीचे वर्णित हैं। **हीमोफीलिया एः** हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया का सबसे आम प्रकार है। यह रक्त में थक्का जमाने वाले कारक VIII के निम्न स्तर के कारण होता है। इस कमी के कारण, चोट लगने, दांतों के इलाज या सर्जरी के बाद रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को जोड़ों में बार-बार चोट लगने या रक्तस्राव की समस्या भी हो सकती है। **हीमोफीलिया बीः** हीमोफीलिया बी तब होता है जब शरीर में रक्त के थक्के बनाने वाले कारक कका स्तर कम होता है। इसके लक्षण हीमोफीलिया ए के समान होते हैं, जिनमें कटने या चोट लगने के बाद लंबे समय तक खून बहना और आंतरिक रक्तस्राव के दौरे शामिल हैं। लक्षणों की गंभीरता रक्त में रक्त के थक्के बनाने वाले कारक ककी मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकती है।

हीमोफिलिया किस कारण से होता है

हीमोफीलिया रक्त में थक्के बनाने वाले कारकों के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जीन में बदलाव के कारण विकसित होता है। जब शरीर में थक्के बनाने वाले कारक का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो थक्का जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और लंबे समय तक रक्तस्राव जारी रह सकता है। अधिकांश मामलों में, यह स्थिति जन्म से ही मौजूद होती है और वंशानुगत आनुवंशिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है। इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं- **वंशानुगत जीन उत्परिवर्तनः** हीमोफीलिया अक्सर माता-पिता से बच्चे में रक्त के थक्के बनने को प्रभावित करने वाले परिवर्तित जीन के माध्यम से फैलता है। जिन परिवारों में हीमोफीलिया का इतिहास रहा है, उनमें कई पीढ़ियों तक कई प्रभावित सदस्य हो सकते हैं। **एक्स गुणसूत्र से जुड़ी वंशानुगतिः** हीमोफीलिया से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। चूंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए एक भी प्रभावित जीन इस स्थिति का कारण बन सकता है। **महिलाओं में वाहक स्थितिः** महिलाएं बिना किसी स्पष्ट लक्षण के परिवर्तित जीन की वाहक हो सकती हैं। एक वाहक मां अपने बच्चों को जीन दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बेटों में हीमोफीलिया या बेटियों में वाहक स्थिति हो सकती है। **नया आनुवंशिक उत्परिवर्तनः** कुछ मामलों में, हीमोफीलिया ऐसे बच्चे में प्रकट होता है जिसका इस विकार का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं होता है। ऐसा प्रारंभिक विकास के दौरान होने वाले एक नए आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होता है।

हीमोफिलिया के शुरूआती लक्षण

हीमोफीलिया के शुरूआती लक्षण अक्सर शिशु अवस्था या बचपन के शुरूआती दौर में दिखाई देते हैं, खासकर जब बच्चा रेंगना, चलना या शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होना शुरू करता है। क्योंकि रक्त सामान्य रूप से नहीं जमता, इसलिए मामूली चोट लगने पर भी सामान्य से अधिक समय तक रक्तस्राव हो सकता है। शुरूआती लक्षणों में शामिल हैंः बार-बार या बिना किसी स्पष्ट कारण के चोट के निशान पड़ना, खासकर मामूली चोट लगने के बाद बड़े-बड़े निशान पड़ जाना। छोटे-मोटे कट या चोट से लंबे समय तक खून बहना जो सामान्य से अधिक समय तक रुकता नहीं है टीकाकरण, इंजेक्शन या मामूली चिकित्सा प्रक्रियाओं के बाद रक्तस्राव होना जोड़ों में सूजन, दर्द या अकड़न, जो जोड़ों के अंदर रक्तस्राव के कारण हो सकती है। बार-बार नाक से खून आना जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो मसूड़ों से खून आना, खासकर दांत निकलते समय या दांतों की देखभाल के दौरान। पेशाब या मल में खून आना, जो आंतरिक रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। खतना या सर्जरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव कई मामलों में, ये लक्षण तब ध्यान देने योग्य हो जाते हैं जब बार-बार रक्तस्राव होता है या रक्तस्राव को रोकने में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है।

हीमोफिलिया का प्रबंधन कैसे किया जाता है

हीमोफीलिया के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य रक्तस्राव को रोकना, रक्तस्राव होने पर उसे नियंत्रित करना और जोड़ों को दीर्घकालिक क्षति से बचाना है। चूंकि यह स्थिति शरीर की स्थिर रक्त के थक्के बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए उपचार का लक्ष्य लुप्त हो चुके थक्के कारक को बहाल करना और जटिलताओं के जोखिम को कम करना है। हीमोफीलिया के प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तरीके निम्नलिखित हैंः रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना मुख्य विधि है। इस उपचार में रक्त के थक्के जमने में असमर्थ रक्त कारक को नस में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। अतिरिक्त रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद मिलती है और रक्तस्राव रुक जाता है। रक्तस्राव होने पर या कुछ चिकित्सीय प्रक्रियाओं से पहले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए यह उपचार दिया जा सकता है। **निवारक उपचारः** कुछ व्यक्तियों में, डॉक्टर रक्त में पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रक्त के थक्के जमने वाले कारकों का इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकते हैं। यह तरीका अक्सर मध्यम से गंभीर मामलों में रक्तस्राव की आवृत्ति को कम करने के लिए अपनाया जाता है। निवारक उपचार जोड़ों को बार-बार होने वाले रक्तस्राव से बचाने में भी मदद करता है, जिससे अन्यथा दीर्घकालिक जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। **मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीः** यह एक नया निवारक उपचार है, विशेष रूप से हीमोफिलिया ए के लिए। यह अनुपस्थित रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों की नकल करके रक्त के थक्के जमने में मदद करता है और इसे नियमित अंतराल पर त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह विधि रक्तस्राव की घटनाओं को कम करती है, जोड़ों को नुकसान के जोखिम को कम करती है, और उन रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो फैक्टर थेरेपी के प्रति अवरोधक विकसित कर लेते हैं। **रक्तस्राव की स्थिति में शीघ्र प्रबंधनः** जटिलताओं से बचने के लिए रक्तस्राव की स्थिति में शीघ्र उपचार महत्वपूर्ण है। जोड़ों या मांसपेशियों के अंदर रक्तस्राव से सूजन, दर्द और गति में रुकावट हो सकती है। तत्काल चिकित्सा सहायता रक्तस्राव को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती है और दीर्घकालिक क्षति के जोखिम को कम करती है। **जोड़ों की देखभाल और फिजियोथेरेपीः** जोड़ों में बार-बार रक्तस्राव होने से धीरे-धीरे जोड़ों के स्वास्थ्य और गतिशीलता पर असर पड़ सकता है। फिजियोथेरेपी और निर्देशित व्यायाम जोड़ों की मजबूती, लचीलापन और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नियमित जोड़ों की देखभाल से पहले हुए रक्तस्राव से जुड़ी अकड़न और असुविधा को कम करने में भी मदद मिलती है।

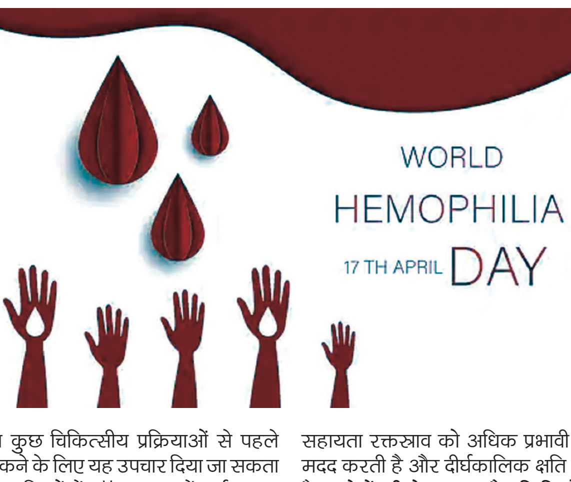

हीमोफिलिया का निदान कैसे किया जाता है

हीमोफीलिया के निदान में लक्षणों के सावधानीपूर्वक आकलन के साथ-साथ रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले प्रयोगशाला परीक्षण भी शामिल होते हैं। हीमोफीलिया के निदान के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं- **चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षणः** डॉक्टर सबसे पहले व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करते हैं, जिसमें लंबे समय तक रक्तस्राव, आसानी से चोट लगना या जोड़ों में सूजन जैसी समस्याएं शामिल होती हैं। करीबी परिवार के सदस्यों में इसी तरह के लक्षणों की जानकारी से आनुवंशिक रक्तस्राव विकार की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है। **रक्त के थक्के जमने की जाँचः** ये जाँचें रक्त के थक्के बनने में लगने वाले समय को मापती हैं और थक्के जमने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाने में सहायक होती हैं। असामान्य परिणाम आगे की जाँच की आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं ताकि इसमें शामिल विशिष्ट थक्का कारक की पहचान की जा सके। **रक्त के थक्के बनने के कारकों का स्तर जांचः** यह जांच रक्त में विशिष्ट थक्के बनने के कारकों के स्तर को मापती है। कुछ थक्के बनने के कारकों का कम स्तर हीमोफीलिया के निदान की पुष्टि करता है और साथ ही इस स्थिति की गंभीरता को निर्धारित करने में भी मदद करता है। **आनुवंशिक परीक्षणः** हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार जीन परिवर्तन की पहचान करने के लिए आनुवंशिक परीक्षण की सलाह दी जा सकती है। यह परीक्षण परिवार में वाहकों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है और परिवार नियोजन के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है। **पारिवारिक चिकित्सा इतिहास का मूल्यांकनः** परिवार के चिकित्सा इतिहास की विस्तृत समीक्षा रक्तस्राव विकारों के पैटर्न का पता लगाने में सहायक हो सकती है। यह जानकारी उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां हीमोफीलिया पीढ़ियों से मौजूद हो सकता है।

शीघ्र निदान क्यों महत्वपूर्ण है

हीमोफीलिया का शीघ्र निदान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इस स्थिति की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाती है, तो बार-बार होने वाले रक्तस्राव से दीर्घकालिक क्षति होने से पहले ही उचित चिकित्सा देखभाल और निगरानी शुरू की जा सकती है। शीघ्र निदान से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं- **गंभीर रक्तस्राव की रोकथामः** शीघ्र निदान से डॉक्टरों को स्थिति की निगरानी करने और रक्तस्राव की घटनाओं को तुरंत प्रबंधित करने में मदद मिलती है, जिससे जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले रक्तस्राव के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। **जोड़ों को नुकसान का खतरा कमः** जोड़ों में बार-बार रक्तस्राव होने से दर्द, सूजन और दीर्घकालिक जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। प्रारंभिक उपचार से जोड़ों को स्थायी नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। **चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए बेहतर योजनाः** हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को सर्जरी, दंत चिकित्सा उपचार या इंजेक्शन के दौरान विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। शीघ्र निदान से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित होते हैं। **दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधारः** नियमित निगरानी और समय पर देखभाल से हीमोफिलिया से पीड़ित व्यक्तियों को बेहतर समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने और इस विकार से जुड़ी जटिलताओं को कम करने में मदद मिलती है। **परिवारों के लिए अधिक जागरूकताः** शीघ्र निदान से परिवारों को इस स्थिति के बारे में जानने, चेतावनी के संकेतों को पहचानने और रक्तस्राव होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने में भी मदद मिलती है।

चंडीगढ़ के मुख्य सचिव ने ऑनलाइन स्व-गणना कर डिजिटल जनगणना को बढ़ावा दिया

जनगणना 2027 में नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

जनगणना 2027 में डिजिटल सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस ने ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक अपना स्व-गणना पूर्ण किया। इस प्रक्रिया में डॉ. नवजोत खोसा, आईएएस, निदेशक, जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़ तथा श्री निशांत कुमार यादव, आईएएस, उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह पहल यूटी प्रशासन की तकनीक के उपयोग द्वारा पारदर्शी, कुशल एवं नागरिक-अनुकूल जनगणना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। मुख्य सचिव द्वारा स्व-गणना कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे नागरिकों को इस सरल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक डिजिटल प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। स्व-गणना के माध्यम से नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ-साथ आंकड़ों की शुद्धता भी सुनिश्चित होती है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रभावी योजना निर्माण एवं नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक आंकड़ों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और जनगणना प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़ तथा उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ द्वारा स्व-गणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागरिकों की सहायता हेतु एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (1855) भी स्थापित की गई है, जहां किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी स्व-गणना पूर्ण करें। एकत्रित की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग में लाई जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा सफलतापूर्वक की गई स्व-गणना, जनगणना 2027 के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे व्यापक जनसहभागिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

गणनाकताओं एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण आरंभ; चंडीगढ़ में स्व-गणना की शुरूआत

चंडीगढ़। आगामी जनगणना अभ्यास की तैयारियों के तहत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आज से केंद्र शासित प्रदेश भर में गणनाकताओं एवं पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण सत्र 29 अप्रैल 2026 तक जारी रहेंगे और इनका उद्देश्य फील्ड कर्मचारियों को सटीक एवं प्रभावी डेटा संकलन हेतु आवश्यक कौशल एवं समझ प्रदान करना है। इस अवधि के दौरान लगभग 2,800 अधिकारियों को संरचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम बैच में 704 प्रशिक्षुओं में से 685 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, जबकि 19 अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। प्रशिक्षण सत्रों में जनगणना प्रक्रियाओं, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, डेटा की शुद्धता तथा फील्ड स्तर पर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि डेटा की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

उपायुक्त-सह-मुख्य जनगणना अधिकारी ने जिला पंचकूला में स्व-गणना अभियान की शुरूआत की

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर प्राप्त की, एसई आईडी
- उपायुक्त ने जिलावासियों से स्व-गणना से जनगणना अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की

उपायुक्त-सह- मुख्य जनगणना अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर जिला में स्व-गणना अभियान की शुरूआत की और एसई आईडी प्राप्त की। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि नागरिकों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व-गणना के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है, जिसमें वे अपनी जानकारी घर बैठे ऑनलाईन भर सकते है। उन्होंने जिलावासियों से आान किया कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और स्व-गणना कर जनगणना 2027 में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि स्व-गणना एक सरल, सुरक्षित और डिजिटल सुविधा है। स्व-गणना करने के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने मोबाईल नंबर से ओटीपी द्वारा लॉगिन कर सकते है। इसके बाद उन्हें अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण चुनना होगा। इसके अलावा डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित कर मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरनी है। सबमिशन के बाद एसई आईडी मिलेगी, जिससे सुरक्षित रखें। प्रगणक आने पर उसे एसई आईडी देनी होगी, जिसके उपरांत प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे।

श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि इस सुविधा से जहां समय की बचत होगी वहीं स्टीक जानकारी और तेज डाटा प्रसंस्करण होगा। उन्होंने कहा कि स्व-गणना एक विशेष सुविधा है। यदि नागरिक स्व-गणना नहीं कर पाते तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित अवधि में प्रगणक लोगों के घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव और नगराधीश एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी जागृति ने भी पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड की और एसई आईडी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला जनगणना समन्वयक श्रीमती मधु यादव भी उपस्थित रही।

पोषण पखवाड़ा 2026: बेहतर पोषण और उज्ज्वल बचपन के लिए सामुदायिक अभियान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पोषण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत सर्किल-52 में पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रभावशाली सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के माध्यम से आयोजित प्ले-बेस्ड लर्निंग गतिविधि ने खेल-खेल में सीखने के महत्व को उजागर किया तथा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित किया। मलोया में नो स्क्रीन अवेयरनेस एवं फैमिली प्ले टाइम गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए स्क्रीन टाइम सीमित करने का संकल्प लिया तथा स्वयं एवं अपने बच्चों में मोबाइल के उपयोग को कम करने के लिए हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।

बापूधाम कॉलोनी में आधारशिला एवं नवचेतना सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, पोषण एवं समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सत्रों में रॉकेट लर्निंग टीम एवं पंजाब विश्वविद्यालय के इंटर्न्स ने सहभागिता की। मनीमाजरा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पोषण, स्वच्छता, संतुलित आहार, एनीमिया की रोकथाम तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई गई। इसके अतिरिक्त आयुष संबंधी जागरूकता सत्र, फूड फोर्टिफिकेशन एवं पोषण के पंच सूत्र का प्रचार-प्रसार, पूरक आहार एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु गृह भ्रमण, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए मोटे अनाज (मिलेट्स) को प्रोत्साहन, स्तनपान की शीघ्र शुरूआत के प्रति जागरूकता, वृद्धि निगरानी तथा 3झ6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

इन सभी पहलों के माध्यम से समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे बच्चों के समग्र विकास एवं बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला द्वारा पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत योग प्रशिक्षण एवं सत्र का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला द्वारा पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत नवीन लघु सचिवालय सेक्टर 1 स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में एक योगा प्रशिक्षण तथा सेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, पंचकूला, डॉ. सविता नेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। योग प्रशिक्षण आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक श्री सचिन कपूर द्वारा करवाया गया जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया तथा स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री सचिन कपूर द्वारा योग सत्र के दौरान विशेष रूप से पवनमुक्तासन श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताया गया, इन श्रृंखलाओं में जोड़ों को सक्रिय करने, गैस व पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा शरीर को लचीला एवं सक्रिय बनाने वाले सरल अभ्यास शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रतिभागियों को ताड़ासन, चक्की चालान आसन, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, बैक बेंडिंग जैसे कई सरल एवं प्रभावी आसनों का अभ्यास करवाया। इन सभी अभ्यासों के माध्यम से शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन आता है, रक्त संचार बेहतर होता है तथा मानसिक तनाव में भी कमी आती है। उन्होंने बताया कि ये सभी आसन अत्यंत सरल हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता है। कार्यक्रम के दौरान सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, जिला पोषण समन्वयक एवं आंगनवाड़ी कार्यकताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, रॉकेट लर्निंग की टीम की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया। इस अवसर पर नियमित योग को दैनिक जीवन में अपनाने तथा पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करना रहा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव ने कालका स्थित नवविवाहित जोड़ों के लिए स्थापित प्रोटेक्शन होम गृह का किया औचक निरीक्षण

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, एडीआर केंद्र, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में कालका स्थित नवविवाहित जोड़ों के लिए स्थापित प्रोटेक्शन होम (सुरक्षा गृह) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोटेक्शन होम के प्रभारी अपने सहायक कर्मचारियों सहित ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए। श्री घनघस ने आगंतुक रजिस्टर का गहन निरीक्षण किया, जिसे उन्होंने पूर्व निरीक्षण के दौरान नियमित रूप से बनाए करने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रोटेक्शन होम में निवास करने वाले जोड़ों की एंट्री की भी जांच की तथा समुचित प्रबंधन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर की समीक्षा की।

निरीक्षण के समय प्रोटेक्शन होम में कोई भी जोड़ा निवासरत नहीं पाया गया। तथापि, लाभार्थियों के मध्य विधिक जागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री घनघस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं से संबंधित पर्याप्त प्रचार सामग्री उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि उक्त सामग्री प्रोटेक्शन होम में सदैव उपलब्ध रहे, ताकि भविष्य में वहां आश्रय लेने वाले जोड़े विधिक साक्षरता संसाधनों से लाभान्वित हो सकें और अपने अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक उपायों के प्रति जागरूक बनें।

इसके साथ ही श्री घनघस ने ग्राम रत्तेवाली का भी दौरा किया, जहां वर्तमान में एक विधिक सहायता क्लिनिक संचालित है। उन्होंने वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, जैसे कुर्सियां, मेज एवं अन्य आवश्यक संसाधनों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उन्होंने पूर्व में निर्देश जारी किए थे, ताकि विधिक सहायता गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें। क्लिनिक के प्रभावी संचालन के लिए इन व्यवस्थाओं की पर्याप्तता का भी विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय निवासियों के साथ संवाद के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विधिक सहायता क्लिनिक का वर्तमान स्थान आमजन के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं है।

पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, जल संरक्षण का भी दिया संदेश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

खंड पिंजौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर भोरिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन पंचकूला की जिला सलाहकार आरजू चौधरी, खंड समन्वयक नरेंद्र मोदगिल तथा सतीश कुमार (पिंजौर) ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं एवं बच्चों को पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने माताओं को संतुलित आहार, बच्चों के समुचित विकास तथा पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी। जल संरक्षण विषय पर अपने विचार रखते हुए नरेंद्र मोदगिल ने ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं को जल बचाने तथा उसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब उपभोक्ताओं को पीने के पानी के बिल एसएमएस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने मोबाइल पर प्राप्त संदेशों के माध्यम से बिल की जानकारी लेकर समय पर ऑनलाइन भुगतान करें। कार्यक्रम के अंत में जल संरक्षण एवं पूरा पोषण, देश रोशन के संदेश के साथ एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शंकुतला देवी, मीना देवी सहित ग्राम पंचायत गणेशपुर भोरिया के अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

हिसार में 20 अप्रैल से 1 मई तक पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप; बुकिंग के लिए रोजाना 40 अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध

चंडीगढ़/हिसार। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, हिसार (प्रधान डाकघर, प्रियत चौक के पास, हिसारझ्र125001) में 20 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 तक पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त तिथियों के लिए अपॉइंटमेंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं और वर्तमान में बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इस कैंप के लिए प्रतिदिन कुल 40 पासपोर्ट अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। जो आवेदक सामान्य श्रेणी (टाट्काल आवेदन को छोड़कर) के तहत नया पासपोर्ट बनवाना या पुनः जारी करवाना चाहते हैं, वे अपनी अपॉइंटमेंट आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

चंडीगढ़ सीबीएसई दसवीं कक्षा का रिजल्ट शानदार, प्रशासन ने की सराहना

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों ने सीबीएसई कक्षा (सत्र 2025-26) के परिणामों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया है। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.25% रहा, जो पिछले वर्ष 81.18% की तुलना में 7.07 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण वृद्धि को दशार्ता है। यह सुधार न केवल शैक्षिक प्रगति का संकेत है, बल्कि प्रशासनिक, शैक्षणिक पहलों एवं सामूहिक प्रयासों की प्रभावशीलता को भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। कुल 9,358 विद्यार्थियों में से 8,257 विद्यार्थियों का सफल होना इस प्रगति का प्रमाण है। इनमें 4,614 बालकों एवं 4,744 बालिकाओं ने परीक्षा दी, जिनमें से क्रमशः 4,050 बालक एवं 4,207 बालिकाएँ उत्तीर्ण रहीं। उपलब्ध आंकड़े यह भी दशार्ते हैं कि बालिकाओं का प्रदर्शन बालकों की तुलना में बेहतर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी और उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। पिछले वर्ष 9,781 में से 7,940 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की तुलना में यह सुधार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 से बढ़कर 21 हो गई, जबकि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 से अधिक रही। संस्थागत स्तर पर भी व्यापक सुधार देखने को मिला, जहाँ 17 विद्यालयों ने 100% परिणाम प्राप्त किए, 23 विद्यालयों का परिणाम 95% से अधिक रहा तथा 10 विद्यालयों ने 90%झ्र95% के बीच परिणाम दर्ज किए। कुल 50 विद्यालयों का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह दशार्ता है कि सुधार अब पूरे शिक्षा तंत्र में व्यापक रूप से स्थापित हो चुका है। यह सफलता संरचित पुनरावृत्ति कार्यक्रमों, रेमेडियल कक्षाओं, सतत मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन जैसी शैक्षणिक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर निगरानी एवं लक्षित रणनीतियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की गई है। श्री गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के माननीय राज्यपाल और प्रशासक, यूटी, चंडीगढ़ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चंडीगढ़ का गौरव बढ़ाया है। मैं सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इस उपलब्धि में हमारे शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों का समर्पण, मार्गदर्शन और अथक परिश्रम अत्यंत सराहनीय है। शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई योजनाबद्ध पहलों और निरंतर प्रयास ही इस सफलता के मूल में हैं। हम मिशन 100% के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रशासन ने यह भी दोहराया कि भविष्य में शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 26 पंचकूला की छात्रा ने हासिल किया जिले में दूसरा स्थान

पंचकूला। बुधवार को सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। जहां अनेक विद्यालयों के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया वहीं राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 26 पंचकूला के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन के साथ विद्यालय का नाम जिले भर में रोशन किया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा।विद्यालय की छात्रा अंशिका ने 96% अंक प्राप्त कर सीबीएसई द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में जिले भर में दूसरा स्थान अर्जित किया। विद्यालय के 24 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए और अधिकतम विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में बोर्ड परीक्षा पास की। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संस्कृति विद्यालय सेक्टर 26 में बालवाटिका और प्रथम कक्षा के लिए आज वीरवार को ड्रॉ के द्वारा प्राप्त आवेदनों में से विद्यार्थियों का चयन किया। ड्रा के दौरान उप जिला शिक्षा अधिकारी नरोत्तम शर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान एवं सदस्य और नव आवेदक अभिभावक और छात्र उपस्थित रहे। आगामी 18 अप्रैल को प्रथम कक्षा और बाल वाटिका का प्रवेश उत्सव विद्यालय में मनाया जाएगा।

पंचकूला की मंडियों में अब तक 2969 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद तथा 2191 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 2969 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 2191 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1148 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 0 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई।

प्राथमिकता वाले 21 जिलों ने लक्षित एवं डेटा-आधारित कार्रवाई के माध्यम से 95-95-99 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियों को क्रियान्वित किया

नाको की राष्ट्रीय रणनीति को गति देते हुए पंजाब ने जिला-आधारित एचआईवी प्रतिक्रिया को बल दिया

सिटी दर्पण संवाददाता
जीरकपुर

एचआईवी नियंत्रण में अधिक प्रभाव वाले जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ठं३ङ्खल्ल' अक्र उङ्खल्ल३१ङ्क' डर्ल्ल२३ङ्खल्ल (नाको) ने आज मोहाली के जीरकपुर में एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पंजाब के प्राथमिक जिलों को एक मंच पर लाकर 95-95-99 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लक्षित एवं डेटा-आधारित कार्रवाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉ. राकेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं महानिदेशक, नाको ने की। इस अवसर पर पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुमार राहुल सहित राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी भी उपस्थित रहे।

डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, पंजाब जैसे राज्यों में, जहाँ इंजेक्शन से नशे का उपयोग एचआईवी संक्रमण को बढ़ावा देता है, इस स्तिथि में हमारी प्रतिक्रिया तुरंत एवं तीव्र होनी चाहिए। डेटा पर आधारित जिला-स्तरीय रणनीतियाँ तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ाव इस इस स्तिथि को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जिलों को अधिक सशक्त बनाना एवं जवाबदेही प्रदान करना राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यह कार्यशाला राज्यों में संचालित संरचित पहलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत और डेटा आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च भार वाले जिलों में एचआईवी कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है। पंजाब, जहाँ एचआईवी प्रसार दर 0.42% हे और अनुमानित 1,10,715 लोग एचआईवी के साथ जीवनयापन कर रहे हैं, इस लक्षित रणनीति के अंतर्गत एक प्राथमिकता वाला राज्य बना हुआ है।

कार्यक्रम के सुदृढ़ कार्यक्रम कार्यवाही हेतु कुल 21 प्राथमिक जिलों-तरण तारण, अमृतसर, मोगा, पठानकोट, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, होशियारपुर, एस.ए.एस. नगर, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर, बरनाला, फरीदकोट, संगरूर, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, फिरोजपुर, बठिंडा, रूपनगर एवं श्री मुक्तसर साहिब-की पहचान की गई है। कार्यशाला में जिला टीमों ने अपनी प्रगति प्रस्तुत की, कार्यक्रम संचालन से जुड़ी चुनौतियों को प्रस्तुत किया तथा एचआईवी की रोकथाम, जाँच एवं उपचार सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु रणनीतियाँ विकसित कीं। राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, श्री कुमार राहुल ने कहा, पंजाब लक्षित और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने एचआईवी प्रत्युत्तर को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यशाला ने जिलों को अपनी रणनीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने और बेहतर सेवा वितरण तथा स्वास्थ्य परिणामों के लिए जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाया है।

कार्यशाला में वरिष्ठ जिला अधिकारियों, जिनमें उप आयुक्त, अतिरिक्त उप आयुक्त, सिविल सर्जन और जिला एचआईवी/एड्स नियंत्रण अधिकारी शामिल थे, की सक्रिय भागीदारी रही, जिसने एचआईवी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समन्वित एवं परिणाम केंद्रित नजरिए को बल मिला। इस एक दिवसीय कार्यशाला ने पारस्परिक सीख को प्रोत्साहित किया तथा जिलों ने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्ययोजनाएँ बनाई। नाको वर्ष 2030 तक एड्स उन्मूलन की दिशा में एक समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। मोहाली कार्यशाला का सफल आयोजन भारत के जिला-आधारित प्रयासों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्राथमिकता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में 95-95-99 लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को गति मिलेगी।